भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र
का
आठवां अखिल भारतीय सम्मेलन

दस्तावेज़

बी टी रणदिवे नगर,
पटना
3-7 मार्च 1994

TIME TABLE
8th ALL INDIA CONFERENCE OF CITU
B T RANADIVE NAGAR, PATNA

2nd March 1994 :

Working Women's Conference 10.AM - 6 PM
Working Committee Meeting/CITU 4.00 PM - 5 PM
General Council Meeting/CITU 5.00 PM - 6 PM

3rd March 1994 :

10.30 AM -	Flag Hoisting
11.00 AM - to 1.30 PM	Inaugural Session 1) Address by the Chairman, Reception Committee 2) Condolence Resolutions 3) Presidential Address 4) Speechs by fraternal delegates from other Central TU leaders
1.30 PM -	Lunch Break
3.00 PM -	Open Rally(Gandhi Maidan,Patna)

4th March 1994 :

9.30 AM - 10.30 AM:	Formation ofthe a) Credential Committee b) Steering Committee Submission of the Report by General Secretary Submission of statement of accounts for the years 1991, 1992 & 1993 By the Treasurer
10.30 AM - 11.30 AM -	Discussion on the Report of the General Secretary
11.30 AM - 12.00 PM -	Tea Break
12.00 - 1.30 PM -	Discussion on G.S Report
1.30 - 3.30 PM	Lunch Break
3.30- 5.30 PM	Discussion on G.S Report
5.30 - 6.00 PM	Tea Break
6.00 - 7.30 PM	Discussion continues

5th March 1994	:	Time schedule same as above	
6th March 1994	:	Delegates to be divided into commissions to consider the Discussion Papers	
7th March 1994	:	9.30 to 11.00 :	Commissions to finalise Report
		11.00 to 11.30 :	Tea Break
		11.30 to 1.30 :	Plenary session - Adoption of Reports of the Commissions
		1.30 to 3.30 :	Lunch Break
		3.30 to 6.00 :	Reply to the Debate by the General Secretary. Adoption of the General Secretary's Report Adoption of statement of Accounts
		6.00 to 6.30 :	Election of New General Council and Office Bearers
		6.30 to 7.00 :	Tea Break
		7.00 to 7.30 :	Election of new Working Committee by the new General Council Summing up speech by the President

स्वागत समिति के अध्यक्ष का. चण्डी प्रसाद का स्वागत भाषण

स्वागत समिति के अध्यक्ष का. चण्डी प्रसाद का स्वागत भाषण

कामरेड अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथिगण एवं

प्रतिनिधि साथियो !

सी.आई.टी.यू. के इस आठवें सम्मेलन में भाग लेने आए हुए विदेशी मेहमानों का भारत की इस ऐतिहासिक नगरी पाटलिपुत्र तथा वर्तमान में पटवा की धरती पर स्वागत करते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है । देश के विभिन्न भागों से आए हुए उन जुझारूसंघर्षशील प्रतिनिधियों का, जिनके पास मजदूर वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा करने हेतु एवं साम्राज्यवादी एजेन्टों के रूप में कार्यरत विघटनकारी शक्तियों, धार्मिक तत्ववादियों एवं साम्राज्यवाद और उसकी एजेन्सियों, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे घुटना टेकू एवं आत्म समर्पणकारी नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह की नयी आर्थिक औद्योगिक नीतियों के विरूद्ध अथक संघर्षों को चलाने का समृद्ध अनुभव प्राप्त है ।

पंजाब के विघटनकारी खालिस्तानियों के विरूद्ध संघर्ष के क्रम में शहीद अपने जांवाज साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए तथा रोजी रोटी की तलाश में गए उन बिहारी मजदूरों का, जिनकी निर्मम हत्या खालिस्तानियों द्वारा की गई भरे दिल से याद करने के उपरान्त पंजाब से आए अपने उन बहादुर प्रतिनिधि साथियों का सिखों के दसवें गरू श्री गोविन्द सिंह जी की जन्म भूमि पटना साहिब में स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, जो अलगाववादी खालिस्तानियों से जुझ रहे हैं । मुझे त्रिपुरा के उन बहादुर प्रतिनिधि साथियों का स्वागत करते हुए भी अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, जिन्होंने कांग्रेस-ई. और त्रिपुरा के अलगाववादियों के सम्मलित आतंक को कुचलते हुए वहां वामपंथी सरकार के गठन में अह्म भूमिका निभायी है ।

साथियों, आपका स्वागत करते हुए हमारा दिल भर जाता है जब हम मंच को अपने संस्थापक अध्यक्ष, प्रखर सिद्धान्तकार एवं मजदूर वर्ग की एकता के प्रबल हिमायती का.बी.टी. रणदिवे, संस्थापक महामंत्री का. पी. राममूर्ति, संस्थापक उपाध्यक्षों का. मु. इस्माईल, का. मनोरंजन राय, का. कमल सरकार जैसे अनेक नेताओं से खाली पाता हूं ।

आज जब हमारी राज्य कमेटी पर सीटू के इस आठवें सम्मेलन की मेजवानी करने की जवाबदेही आ पड़ी है तो हमें बिहार के किसानों खेत मजदूरों के नेता का. रामानन्द सिंह, जिनकी हत्या अपराध कर्मियों ने वैसे समय में कर दी जब वे

कांग्रेसी तानाशाही के विरूद्ध संघर्ष के क्रम में उसके एक बड़े नेता के विरूद्ध कटिहार लोक सभा चुनाव लड़ने की तैयारी में संलग्न थे, की कमी बहुत ही खल रही है। वे हमेशा सीटू के संगठन और उसके संघर्षों के संचालन में एक सहयोद्धा के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे तथा किसान-मजदूर एकता को अमली जामा पहनाते थे आज इस अवसर पर हम मजदूर संघ से आये हुए उन नेतृत्वकारी साथियों जैसे लौह असस्क खदान मजदूरों के नेता का. नकुल गुहा, झरिया कोयला खदान के मजदूरों के नौजवान कार्यकर्ताओं का. रामदेव सिंह, जिनकी हत्या सभा के लिए प्रचार करते समय करमचंद थापर के गुंडों ने कर दी थी, को याद किए बिना नहीं रह सकते जिन्होंने सीटू के प्रारंभिक दिनों में उसे संगठित करने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था।

आज के आयोजन के अवसर पर मैं बिहार के उन बहादुर किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने सामन्तवादी तत्वों तथा महाजनी गुंडों के वितरूद्ध भूमि मुक्ति संघर्षों का संचालन किया है तथा सीटू के प्रारंभिक दिनों में हमारी भरपूर सहायता की। इनमें से विशेषकर रांची जिले के नौजवान किसान कार्यकर्ता का. द्वारिका महतो, दानी दत्त लक्ष्मीकांत स्वांसी, बक्सर के का. ज्योति प्रकाश, खगड़िया के का. आनन्दी सिंह सहित अभी हाल के भूमि संघर्षो में शहीद हुए पूर्णियां जिले के राजेन्द्र हेम्ब्रम, फागु वासुकी, ककरू मियां, सगीर मियां, समस्तीपुर जिले के किसान नेता का. गुणेशवर सिंह, दरभंगा के का. महेश्वर सिंह, रामशरण चौवाल, मधुबनी जिले के का. रामअवतार यादव, कां. विष्णु देव यादव, रांची जिले के बंशीधर मुंडा, कांडे मुंडा, गोपाल सिंह मुंडा आदि लगभग दो दर्जन शहीद साथियों को याद किए और उनके प्रति सम्वेदना प्रकट किए बिना नहीं रह सकता जिन्हें सामन्तों और उनके तथाकथित नक्सली गुंडों तथा वर्तमान राज्य सरकार की पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा है। इसी क्रम में हिलसा (नालन्दा जिला) प्रखंड पर किए गए प्रदर्शन में अंचला धिकारी के इशारे पर पुलिस की गोली से शहीद हुए का. गोविन्द प्रसाद, अधिवक्ता तथा मोतिहारी में जन प्रदर्शन के दरम्यान शहीद का. उस्मान खां को कैसे भूला जा सकता है। उन्हें भरे दिल से याद करते हुए किसान संघर्षों और जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अथक संघर्ष चलाने के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार के मजदूर वर्ग ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए सम्प्रदायवादी तत्वों के विरूद्ध संघर्ष में भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया है, और राज्य के सभी वाम जनवादी तथा धर्म निरपेक्ष शक्तियों के साथ मिलकर उनका मुकाबला किया है। 6 दिसम्बर 92 की घटना के ब्राद सम्प्रदायवादी कुचक्रों के विरूद्ध आगे बढ़कर संघर्ष चलाने में भी हमने अपनी शानदार भूमिका निभायी है। इस मामले में बिहार की सभी वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के सहयोग से राज्य की श्री लालू प्रसाद सरकार की भूमिका भी सराहनीय रही है, और उसने सम्प्रदायवादी शक्तियों की कमर तोड़ने तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने का उल्लेखनीय कार्य किया है। साथियों, हमारा राज्य देश के अन्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में अव्वल है। हमारी कृषि अभी भी पूरी तरह मौसम पर आधारित है। बिहार आज भी सामंती जकड़ में कसा हुआ है। आजादी के 47 वर्षों के बाद आज भी हमारे यहां हजारों एकड़ भूमि रखने वाले भूमि चोर मौजूद हैं। उनके भंयकर सामाजिक आर्थिक शोषण के नीचे बिहार के मेहनतकश गरीब किसान तबाह और वर्वाद हैं। मौसम पर निर्भरता के कारण कभी हमारे गांव बाढ़ और कभी सुखाड़ के लगातार शिकार होते रहे हैं।

किन्तु इसके विपरीत हमारा राज्य, प्राकृतिक सम्पदा से भरा पूरा है। इसकी धरती में कोयला, अबरक, चूना, लोहा, तांबा से लेकर यूरेनियम और मैंगनीज जैसी बहुमूल्य खनिज सम्पदा छिपी पड़ी है। आजादी के बाद विकास के प्रारंभिक चरण में यहां कोयला इस्पात, विधुत, खाद, भारी इंजीनियरींग के बड़े उद्योग खोले गए जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक उद्योग में कार्यरत मजदूरों की संख्या की दृष्टि से हम अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर हैं। फिर भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या की दृष्टि से भी हमारा स्थान ऊपर हैं।

भारत सरकार की नयी औद्योगिक और आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप बरौनी और सिन्द्री का खाद कारखाना, रांची का हैवी इंजीनियरिंग उद्योग, घाटशिला का हिन्दुस्तान कॉपर कारपोरेशन, इंडियन केबुल कम्पनी लि. जैसे संगठित सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उपक्रम बंदी के कगार पर खड़े हैं। माईका और लौह अयस्क खदानों की स्थिति भी बंदी की है। 12000 छोटे और मंझोले उद्योग बंद हो चुके हैं। हमारे राज्य का हथकरघा उद्योग प्राय: नष्ट हो चुका है। बीड़ी उद्योग में कार्यरत 3 लाख मजदूरों को आधे दिन का भी काम उपलब्ध नहीं है। नतीजतन लाखों मजदूर बेरोजगारी के आलम में भूखे मरने को मजबूर हैं। साथियों, इन्हीं परिस्थतियों में हमारी स्वागत समिति ने अपने साधन और सीमाओं के अन्तर्गत आपके आवास और खाने पीने की व्यवस्था की है। वेशक ऐसी स्थिति में आपको बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए हम आपके प्रति क्षमाप्रार्थी हैं। इस प्रकार के बड़े आयोजन को सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में तजुर्वे और साधन की कमी और हमारी सांगठनिक कमजोरियों को मद्दे नजर हमें माफ करते हुए अपना ध्यान मुख्य कार्य भारों पर केन्द्रित करेंगे।

साथियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सम्मेलन के आयोजन में आप सभी साथियों से हमें प्रारंभ से ही सहयोग और प्रोत्साहन मिला है।

विशेष कर हमारे पड़ोसी राज्य और हमारे अग्रज तथा संघर्षों के तजुर्वा से समृद्ध पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी तथा उसके अध्यक्ष एंव महामंत्री का. निरेन घोष एवं का. चितव्रत मजुमदार ने अपने कलाकारों और दीवार लेखन करने वाले नौजवान साथियों को भेजकर हमारी भरपूर सहायता की है और हमें प्रोत्साहित किया है। इस गुरुत्तर कार्यभार को पूरा करने में इनसे जो सहायता प्राप्त हुई है, उसके लिए हमारी स्वागत समिति उनका हार्दिक अभिनन्दन करती है।

हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि आप प्रतिनिधि साथी हमारी स्थिति को देखकर हमारी त्रुटियों को नजरनंदाज करते हुए तथा सभी कष्टों को सहते हुए देश के मजदूर वर्ग को नयी दिशा प्रदान करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य को पूरा करेंगे।

क्रांतिकारी अभिनन्दन के साथ,

आपका साथी

(चण्डी प्रसाद)

अध्यक्षीय भाषण

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियों एवं अतिथियो,

हमारा सातवां सम्मेलन 13-17 फरवरी 1991 को कलकत्ता में हुआ था। हमारे इस सम्मेलन की समीक्षा अवधि एक ऐसी अवधि रही है जब अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों में रौंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं घटीं। इस अवधि के दौरान देश-विदेश में ट्रेड यूनियन आंदोलन की जबरदस्त गतिविधियां देखी गईं। महासचिव की रिपोर्ट में इन सभी पर विस्तार में प्रकाश डाला गया है। मैं केवल कुछ विशेष मुद्दों पर ही स्वयं को केन्द्रित रखना चाहूँगा।

इससे पूर्व कि मैं अपना भाषण शुरू करूं, आईये हम उन साथियों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करें जो इस अवधि के मध्य हमसे बिछुड़ गए। हमारे दो उपाध्यक्ष कामरेड मनोरंजन राय और कामरेड कमल सरकार, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अनेक गणमान्य नेता और कई अन्य साथी जिन्होंने हमारे संगठन के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान डाला है, आज हमारे मध्य नहीं रहे हैं। मैं अपने उन साथियों के प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा जिन्होंने जनता तथा मजदूर वर्ग के हितों की रक्षार्थ चले अनेक संघर्षों में अपने प्राण न्योछावर किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी इस अवधि में अनेक प्रमुख नेता हम से बिछुड़ गए हैं। उनकी याद सदा हमारे दिलों में समाई रहेगी हम उन सभी का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा प्रण करते हैं कि हम महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते रहेंगे।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वी यूरोप तथा पूर्व सोवियत संघ में समाजवाद को लगे धक्के सम्पूर्ण विश्व के लिये दुखद घटनाएं थीं। हमारे सातवें सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण देते समय कामरेड ज्योति बसु ने इसका उद्धरण दिया था। उस समय केवल पूर्वी यूरोप में ही भारी परिवर्तन हो रहे थे। किन्तु सोवियत संघ की घटना ने तो हम सब को हिला कर रख दिया है। तथापि अब इन देशों में समाजवादी समाज व्यवस्था नहीं रही है और वे पूंजीवादी मकड़जाल में फंस चुके हैं। सामयिक दृष्टि से प्रचंड परिवर्तन के फलस्वरूप विश्व स्तर पर साम्राज्यवाद के पक्ष में शक्तियों का संतुलन हो गया है। वे लोग अब जोर-शोर से कह रहे हैं कि समाजवाद मर चुका है और मानव विकास के लिये केवल पूंजीवादी व्यवस्था ही बनी रह सकती है।

शक्तिशाली सोवियत संघ ने सदा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यावस्था (संतुलन) बनाए रखी और वह सदा साम्राज्यवादी दबावों एवं आक्रमणों के विरोध में दुर्बल राष्ट्रों का विश्वसनीय साथी बना रहा था। उसके पराभव से सारा विश्व भौंचक रह

गया और मजदूर वर्ग तो अपने उस माडल से वंचित हो गया जिसे सामने रख कर वह पूंजीवाद विरोधी अपने संघर्ष का परचम ऊंचा उठाए हुए था। सोवियत संघ में समाजवाद की उपलब्धियों के कारण हमारे देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन भी उसकी ओर आकर्षित हुआ था। वहां पर मजदूर वर्ग ने ऐसे अधिकार प्राप्त किये थे जिनकी पूर्व कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उसने काम का अधिकार, निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास, सामाजिक सुरक्षा, तथा महिल्लाओं के लिये समान अधिकार इत्यादि प्राप्त किये थे। इसलिये ट्रेड यूनियन आंदोलन भी इस तथ्य को कभी भुला नहीं सकेगा कि पिछड़ा हुआ रूस बहुत ही कम समय में विश्व के बड़े औद्योगिक राष्ट्रों में से एक बन गया था, उसने दृितीय विश्व युद्ध में विश्व पर आधिपत्य स्थापित करने के लिये लालायित नाजीवादी शक्तियों को पराजित करने हेतु संघर्ष को प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया था और इसके लिये अतुलनीय बलिदान दिये थे।

सोवियत संघ ने विश्व की बड़ी शक्ति बन कर शक्तियों का संतुलन बदल डाला था और वह मुक्ति युध्दों तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों जिनमें हमारे देश का स्वाधीनता आंदोलन भी शामिल है, का घोर समर्थक एवं सहयोगी बन गया था। वह भी एक तथ्य है कि दुसरी औद्योगिक शक्तियों उसे राष्ट्रीय उद्योगों की आंतरिक संरचना के निर्माण हेतु औद्योगिकीय एवं वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया था। इस पर भी सोवियत संघ आगे बढ़ा, उसने निश्चलता को स्थिति को समाप्त किया। उसने हमारे देश के औद्योगिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। इसलिये समाजवाद के लगे धक्कों का प्रभाव हमारे देश के ट्रेड यूनियन आंदोलन पर भी पड़ने की सम्भावना थी। तथापि थोड़े ही समय के अनुभवों ने समाजवाद की श्रेष्ठता और साम्राज्यवाद के आक्रमक चरित्र को प्रमाणित कर दिया है। उसने 'पूंजीवादी ही सभी समस्याओं का प्रत्युत्तर है' के झूठे दावे की कलई भी खोल दी है।

फारस की खाड़ी का संकट और खतरनाक युद्ध, पूर्व युगोस्लाविया में गृह युद्ध, अफगानिस्तान में संकटपूर्ण स्थिति, सोमालिया में साम्राज्यवादी हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का अमरीकी कठपुतियां बन जाना, विकासशील देशों की मुसीबतों एवं कष्टों में दिलचस्पी न लेना, इत्यादि घटनाओं ने साम्राज्यवाद के खतरनाक कुकृत्यों का प्रदर्शन ही किया है। भविष्य कैसा होगा, इसकी कल्पना तो उक्त घटनावली को पढ़ कर ही की जा सकती है। आज अमरीका व्यवहारिक रूप से सभी राष्ट्रों के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के सभी पक्षों में अपनी शर्तें थोप रहा है। उसका सदा एक मात्र उद्देश्य अपने नग्न व्यापारिक एवं सैनिक हितों की सेवा करना होता है - यह सब नयी विश्व व्यवस्था के नाम पर किया जा रहा है। समाजवाद को धक्के लगने के पश्चात् साम्राज्यवाद के आगे कोई अवरोध ही नहीं रहा और वह मनमाने ढंग से तृतीय विश्व के देशों की लूटमार एवं डकैती कर रहा है। वह औपनिवेशिक शोषण की नयी-नयी विधियों को प्रयोग में ला रहा है। पूंजीवाद का दुस्साहस पहले कभी इतना नहीं बढ़ा था। उसने सभी राष्ट्रों में मजदूर वर्ग पर अपने हमले तेज का दिये हैं। श्रमिकों की कामकाजी एवं जीवन स्थितियों पर तीव्रतर हमला जारी है और शताब्दियों तक संघर्ष करके एवं असंख्य बलिदान देकर उसने (श्रमिकों ने) जो अधिकार प्राप्त किये थे, उन पर भी हमले किये जा रहे हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद सभी मामलों में अपनी सरदारी थोपने का प्रयास कर रहा है। वह दूसरे राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का अतिक्रमण कर रहा है। वह अपनी राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक तानाशाही की विश्व व्यवस्था के लिये काम कर रहा है।

अमरीका ने विश्व भर में अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए थे, यूरोप में नाटो के नाम से सैनिक गठजोड़ किया था, और यह सब कुछ उसने सोवियत खतरे के नाम पर ही किया था। अब सोवियत संघ का विखण्डन होने और समाजवाद को धक्के लगने के पश्चात् खतरे का कोई वैध तर्क नहीं रहा है। तथापि विश्व भर में अपने सैनिक अड्डों और नाटो गठजोड़ को समाप्त करने के स्थान पर अमरीकी प्रशासन कोई न कोई बहाना बना कर अपने सैनिक अड्डों को बनाए रख रहा है, वहां पर अपनी सेनाओं उसने यथावत बनाए रखी हैं और कुछ मामलों में तो उसने सैनिकों में मामूली-सी कमी ही की है। अब नया बहाना गढ़ा जा रहा है कि रूस में मिस्टर ज़िरनोवस्की के नेतृत्व में नाजीवादी शक्तियां सिर उठा रही हैं। इससे न केवल रूस अपितु सम्पूर्ण युरोप के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। मास्को तथा ब्रसेल्स वार्ताओं में बोरिस येलत्सिन एवं बिल क्लिटन के साथ पूर्वी युरोपीय देशों के नेताओं की नवीनतम विचार विमर्श के फलस्वरूप जो नयी सहमति बनी है, उसके अनुसार नाटो बना रहेगा, पूर्वी युरोपीय देश उनके नये सहयोगी होंगे और निश्चित अवधि में उसके द्वार रूस के लिये भी खोल दिये जाएंगे। बिल क्लिटन यूक्रेन के साथ वहां पर रखे हुए नाभिकीय शस्त्रों को समाप्त करने समझौता कर सके हैं और उसे नाभिकीय अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर सके हैं। इस प्रकार अमरीका अपने बृहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिये बोरिस येलत्सिन को अपना कनिष्ठ सहयोगी बनाने का प्रयास कर रहा है। नाटो के नाम पर विश्व के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में "शांति बल" रखे जा रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां हस्तक्षेप किया जा सके। इस प्रकार अमरीका रूस को कच्चे माल और प्रतिभा शक्ति के अपने पिछवाड़े (गोदाम) के रूप में परिवर्तित करने की योजना बना रहा है क्योंकि बोरिस येलत्सिन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिये अमरीका पर निर्भर करने को विवश हैं और दिन प्रतिदिन रूसी जनता से अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं।

पश्चिमी एशिया में इराक के ऊपर अमानवीय आक्रमण करने के पश्चात् भी अमरीका ने उसकी आर्थिक नाकाबंदी जारी रखी हुई है। इस प्रकार तेल की दृष्टि से समृद्ध इस क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनाई गई है ताकि वे भारी स्तर पर अपने सैनिक अड्डों को बनाए रख सके और उस क्षेत्र पर उन्हीं का (अमरीका) आधिपत्य स्थापित रहे।

लातिनी अमरीका तथा कैरेबियन क्षेत्र में अमरीका का आर्थिक आधिपत्य जारी रखने के लिये अनेक विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। सैनिक प्रभुत्व को बनाए रखा जा रहा है ताकि उस क्षेत्र के देश उसके आगे दबे रहें।

समाजवादी क्यूबा को दासत्व की ओर धकेलने के लिये अमरीका हर हर्बा प्रयोग में ला रहा है। वह जासूसी करता है,

भयादोहन करता है, आर्थिक नाक़ाबंदी करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव पारित किये जाने पर भी उसने क्यूबा की आर्थिक नाकाबंदी जारी रखी हुई है। सैनिक हस्तक्षेप की धमकियां भी दी जा रही हैं।

विश्व को परमाणु शस्त्रों से मुक्त करने के नाम पर अमरीका जहां स्वयं अपने पास परमाणु शस्त्रों के अपार भण्डार जो अनेक बार धरती को बर्बाद का सकते हैं, वहीं दूसरों से अपेक्षा रखता है या उन्हें विवश करता है कि वे अपने पास कोई परमाणु शस्त्र न रखें। यहां तक कि विकास कार्यों के लिये भी परमाणु परीक्षण न करें। वह सभी देशों को जिनमें भारत भी शामिल है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश कर रहा है।

उत्तरी कोरिया के विरुद्ध उसकी धमकियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब तो अमरीका ने घोषणा की है कि यदि उत्तरी कोरिया ने अपने परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया तो वह उसके विरुद्ध युद्ध करेगा। वह कश्मीर पर अपना दावा निरंतर करते रहने के लिये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है और अन्ततः वह कश्मीर में जनमत कराने की वकालत करने की सीमा तक भी चला गया है ताकि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए।

वह एशियाई राष्ट्रों के बीच सहयोग से भी प्रसन्न नहीं हैं। वह भारत तथा चीन के मध्य सम्बन्धों में सुधार को भी संहेद की दृष्टि से देख रहा है। वह नहीं चाहता कि दक्षिणी एशिया के देश अमरीकी प्रभुत्व के विरोध में अपना प्रभावी गठजोड़ बना लें। इसे रोकने के लिये वह राजनीतिक, आर्थिक और अन्य कदम उठा रहा है।

तथापि हम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि विश्व के एक बड़े राष्ट्र के रूप में भारत जो चीन के पश्चात् सबसे बड़ा राष्ट्र है, को वैश्वीकरण सम्बन्धी अमरीका रणनीति के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

पिछले 2-3 वर्षों से औद्योगिक पूंजीवादी विश्व सबसे लम्बे और यदि यह कहें कि सर्वाधिक गहरे मंदे की चपेट में है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगा ऐसा भयानक मंदा पिछले 60 वर्षों में शायद ही पहले कभी आया हो। सभी विकसित पूंजीवादी देशों में औद्योगिक उत्पादन निश्चलता की स्थिति में है और कुछ मामलों में तो उसमें केवल सांकेतिक वृद्धि ही देखी गई है। "विश्व की आर्थिक सम्भावनाएं 1993" में विकसित पूंजीवादी देशों के सम्बन्ध में जी डी पी के अधोलिखित आंकड़े दिये गए हैं।

पिछले तीन वर्षों से अनेक औद्योगिक देशों में विकास दर नगण्य रही है। जापान, जर्मनी, फ्रांस जो सबसे बड़े पूंजीवादी देश हैं, में विकास नगण्य है। केवल यू.के. (ब्रिटेन) की विकास दर 1.8% रही।

सभी विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती चली जा रही है। यहां तक कि अमरीका में भी जहां

अर्थतंत्र में मामूली सुधार हुआ है, बेरोजगारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जर्मनी में यह दर 12% से ऊपर जा चुकी है, फ्रांस में यह 12% है और अगले वर्ष तक इसमें और वृद्धि होने की सम्भावना है। यूरोपीय आर्थिक भाईचारे के देशों में कुल बेरोजगारी 170 लाख है और इस वर्ष के मध्य तक इसके 200 लाख हो जाने की सम्भावना है। जापान सहित अन्य विकसित पूंजीवादी देशों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। अनेक औद्योगिक दैव संकट में है और लाखों श्रमिकों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। उन में से अनेक अपनी उसे कम वेतन वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनरल मोटर्स, आई बी एम इत्यादि गहरे संकट में फंसे हुए हैं। केवल जापान में ही इस संकट के कारण 235 लाख श्रमिकों के रोजगार पर तलवार लटक रही है। इस संकट से 60% औद्योगिक इकाईयां प्रभावित हुई हैं। इसी बीमारी का निदान उच्च प्रौद्योगिकी लाकर और अधिक आधुनिकीकरण करने के रूप में ढूंढा जा रहा है जिसका अर्थ रोजगार में और कमी लाना ही है। इन विकसित पूंजीवादी देशों में बेरोजगारों के लिये रोजगार पाने के अवसर तो बहुत ही कम हैं। सभी विकसित पूंजीवादी देशों में अब श्रमिकों के वेतनों पर धावा बोला जा रहा है। इसका आरम्भ कल्याण योजनाओं जिन पर कुल खर्च सकल वेतन का केवल 1/3 या 1/4 भाग होता है, पर हमला करके किया जारहा है। केवल श्रमिकों के वेतनों में कमी करने का प्रस्ताव ही विचाराधीन नहीं है अपितु नौकरी का स्थायित्व को भी समाप्त किया जा रहा है और श्रमिकों के कानूनी अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इन दिनों स्थाई श्रमिकों की भर्ती करने के स्थान पर रोजगार को अस्थाई बनाने, वेतन तथा अन्य सुविधाओं में कमी लाने का रुझान चल रहा है। अत: पूंजीवादी विश्व के उच्च प्रौद्योगिकी वाले समाज "जिन्हें मानव विकास की चिरंतन व्यवस्था" के माडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अपना विकृत चेहरा दिखा रहे हैं। इन देशों में मजदूर वर्ग और लाखों मेहनतकश लोगों को अकथनीय कष्टों की भट्टी में झोंका जा रहा है। सांस्कृतिक स्तर नीचे गिर रहा है, रंगभेदी तनाव में वृद्धि हो रही है, खतरनाक किस्म की गुंडागर्दी पनप रही है अर्थात् ये सभी व्याधियां बढ़ रही है और वह भी भयभीत करने देने वाली गति से। रूस तथा पूर्व समाजवादी देशों की स्थितियां तो अत्यंत दयनीय हैं। अब उन्हें स्वयं पूंजीवादी स्वर्ग की किवदंतियों के बारे में सत्य का ज्ञान हो रहा है।

इन देशों में ट्रेड यूनियन आंदोलन को मजदूर वर्ग की बड़ी हड़तालों का नेतृत्व करना पड़ रहा है। हम यहां विस्तार में उसकी चर्चा नहीं करना चाहेंगे। वे लोग जो यह समझते थे कि वे पूंजीवादी संरचना में रह कर सामूहिक सौदेबाजी करके मजदूर वर्ग का जीवन स्तर अच्छा बना सकते हैं आज उनका मोह भंग हो चुका है और अब वे कोई भी सुझाव देने की स्थिति में नहीं रहे।

आर्थिक संकट जो विकसित पूंजीवादी देशों के सिर पर मंडरा रहा है, ने उन्हें बाजार के लिये भारी युद्ध करने पर विवश कर दिया है। अमरीका, जापान तथा जर्मनी अपने उत्पादों के लिये अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे उनकी बिक्री कर सकें।

ये विकसित देश तृतीय विश्व के देशों में बाजार को हस्तगत करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गाट तथा उनके जैसे अन्य हथकंडे अपना रहे हैं ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय, नाफ्टा, एसियान तथा एपेक्स इत्यादि सभी उसी प्रक्रिया के भाग हैं किन्तु अपने-अपने प्रभाव के क्षेत्र विकसित करने के प्रयासों के कारण इन देशों में तनाव उत्पन्न हो चुका है । इसकी नवीनतम उदाहरण बिल क्लिंटन की जापान यात्रा से देखने को मिल जाती है । जापानी प्रधानमंत्री मोरिहीरो होसोकोवा के साथ वार्ता के समय अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रयास किया था कि किसी तरह जापान अपने अतिरिक्त व्यापार में 500 खरब डालर की 12 फरवरी 1994 तक कमी कर दे । अमरीका चाहता है कि जापान कारों, आटो पार्टस्, मेडिकल तथा दूरसंचार उपकरणों जैसे अमरीकी उत्पादों के लिये आयात लक्ष्य निर्धारित करे । वार्ता विफल रही । अमरीका ने जापान के विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने की धमकी दी है ।

गाट वार्ताएं जो सात से भी अधिक वर्षों तक चलती रही हैं, भी एक ऐसा क्षेत्र रही हैं जहां इन देशों के मध्य तनाव में निरंतर वृद्धि होती रही और अन्ततः दूसरे देशों को अमरीका दबाव के आगे झुकना पड़ा और 15 दिसम्बर 1993 को एक समझौता किया गया । यह समझौता तृतीय विश्व के हितों के विरुद्ध है । समझौते के अनुसार किसी भी देश में विदेशी पूंजी निवेश के लिये कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । कृषि उत्पाद भी इन समझौते की परिधि में आ जाते हैं ।

विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां नये बीजों और पौधों की नयी-नयी किस्मों के शोध कार्य पर नियंत्रण करने के समर्थ हो सकेंगी । यह काम हमारे कृषि क्षेत्र का है । इससे पौध-नियमों का अतिक्रमण होगा । वे हमारी गतिविधि के किसी भी क्षेत्र में चाहे वह मशीन-निर्माण हो, दवा उद्योग या अन्य निर्माता क्षेत्र, शोध एवं विकास, बैंकिंग, बीमा तथा अर्थतंत्र के दूसरे क्षेत्र ही क्यों न हों, हस्तक्षेप कर सकेंगी ।

व्यापार प्रतिबंध उनकी इच्छा के अनुसार ही लागू किये जा सकेंगे जो हमारे लिये अलाभप्रद होंगे । संक्षेप में, काम के सम्बन्ध में उनकी रणनीति विदेशी बहुराष्ट्रीयों के लिये पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और सरकार पर प्रतिबंध लागू करना है । भारत सरकार इस रणनीति के आगे झुकती ही चली जा रही है ।

साम्राज्यवादी शक्तियां अपनी नयी प्रौद्योगिक शक्ति का प्रयोग इन्हीं उद्देश्यों के लिये ही कर रही हैं । अमरीका द्वारा तृतीय विश्व के देशों के विरुद्ध विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हथकंडों को प्रयोग में लाया जा रहा है ।

इसलिये ट्रेड यूनियनों को अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा तथाकथित 'नयी विश्व व्यवस्था' के नाम पर विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने हेतु जिन हथकण्डों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें समुचित रूप से समझना होगा । ट्रेड

यूनियनों को सभी देशभक्त शक्तियों को लामबंद करके इन नये साम्राज्यवादी हमलों का सामना करना होगा। मैं नहीं समझता कि मेरे लिये इसके महत्व पर बल देने की कोई आवश्यकता है।

मीडिया तथा प्रेस द्वारा हमें भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विश्व बैंक तथा कोष निदेशित नीतियों की सफलता की कहानियां प्रतिदिन सुनाई जाती हैं। वे उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को अक्षरश: कार्यरूप देना चाहते हैं। उन्हें इसके दुष्परिणामों की भी चिंता नहीं है। हमारे अनुभव तथा तथ्य इसके सर्वथा विपरीत कहानी कहते हैं। नवीनतम उदाहरण उन 'लाभों' की खुराक है जिन्हें बजट पूर्व जनता के सामने 'उपहार' स्वरूप परोसा जा रहा है। चावल, गेहूं, चीनी, पेट्रोल, डीज़ल तथा कुकिंग गैस के मूल्यों में वृद्धि होने से जनता का जीवन और दूभर हो गया है। इसके माध्यम से जनता पर 6000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया है। पेट्रोल तथा डीज़ल के मूल्यों में वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों में अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में जबरदस्त उछालाआ जाएगा। रेलवे और वायु परिवहन की भाड़ा एवं किराया दरों में वृद्धि होने से और मूल्य वृद्धि होगी। इसे भी आर्थिक दबावों के नाम पर न्यायोचित हराया जा रहा है। तथापि मूल्य वृद्धि का भारी बोझ मूल्य सूचक अंक में प्रतिबिम्बित नहीं होगा।

संसद के मामले में तो सत्ताधारी वर्ग लगभग निश्चिंत सा हो गया है। वह अब बजट प्रस्तावों के लिये संसद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता को भी अनुभव नहीं करता। कांग्रेस-इ अब बजट से पहले ही लोगों पर आर्थिक बोझ डालने वाला माडल बन गई है तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। संसद को मात्र सजावटी स्थल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि उस अध्यादेश से भी हो जाती है जिसके अन्तर्गत खनिज सम्पदा देशी तथा विदेशी निजी हाथों में सौंपी गई है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयर लाइन्स के मामले में भी यही हुआ है। आईये, हम देखें कि पिछले तीन वर्षों 1991-92 से 1991-94 में हमारे अर्थतंत्र का क्या हाल हुआ है।

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की अपेक्षा कृषि, उद्योग तथा जी एन पी की सामान्य विकास दरें कहीं कम थीं।

(2) सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि की अपेक्षा मुद्रा प्रसार की सामान्य दर कहीं अधिक थी।

(3) सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत सरकार के सकल ऋण भार देशी तथा विदेशी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जबकि सकल घरेलू उत्पादन में 56.73% से 56.93% तक मामूली-सी वृद्धि दर्ज की गई।

(4) 1993-94 के वार्षिक बजट का घाटा बहुत अधिक होगा। शायद ही घाटे का प्रतिशत कभी इतना अधिक रहा हो। वह उससे भी अधिक होगा जिसका वादा 1993-94 के लिये किया गया है।

(यह मूल्यांकन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री भानु प्रताप सिंह ने फ्रंटलाइन जिल्द II संख्या 4 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया है ।)

ये आकट्य तथ्य भारत सरकार द्वारा किये जा रहे उन दावों को झुठला देते हैं कि हमारा अर्थतंत्र तेजी से विकास कर रहा है । 1993-94 के लिये उपलब्ध उत्पादन आंकड़े और भी परेशान करने वाले हैं ।

1993 के पहली छिमाही के मध्य औद्योगिक उत्पादन के साधारण सूचकांक में 1.6% की वृद्धि दिखाई गई थी । निर्माता उद्योग ने केवल .6% का सुधारा दिखाया था जो पिछले 40 वर्षों में सबसे कम था । खनन में 1.1% की कमी हुई जबकि विद्युत उत्पादन 8.6% बढ़ा । विशेष रूप से उल्लेख किये जाने वाली बात यह है कि पूंजीगत-माल के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा 8% की कमी हुई । कच्चे तेल का उत्पादन 2.8% तक कम हुआ । उर्वरक (नाइट्रोजन) का उत्पादन 1.7% गिरा । कृषि उत्पादन में 1993-94 वर्ष में 2.3% की वृद्धि होने की सम्भावना थी जबकि पिछले वर्ष उसमें 5% वृद्धि हुई थी । केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तेजी से लगाए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 का सकल राष्ट्रीय उत्पादन 3.8% होगा जबकि पिछले वर्ष इसका आंकड़ा 4% था । इसलिये पिछले तीन वर्षों में जिसे तथाकथित नयी आर्थिक नीति की अवधि कहा जा सकता है, देशी की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है । इसकी अपेक्षा इन नीतियों ने हमारे अर्थतंत्र पर विपरीत प्रभाव ही डाला है । नवीनतम उपलब्ध स्थिति इस प्रकार है:

सूचकांक संख्या औद्योगिक उत्पादन (1980-81 = 100)	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
सामान्य सूचकांक	8.6	8.4	-0.2	1.6	1.7
खनन एवं उत्खनन	6.3	4.5	-0.4	1.7	-0.3
निर्माता उद्योग (मैन्यूफैक्चरिंग)	0.6	9.1	-1.8	0.9	0.7
विद्युत	10.8	7.8	8.5	4.9	8.7

नयी नीतियों के नाम पर अपनाई गई विभिन्न नीतियों पर सरसरी दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि इससे हमारे अर्थतंत्र और राज्य व्यवस्था के लिये गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ।

विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रवेश देने के प्रारम्भिक कदम के रूप में विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम, एकाधिकारी तथा प्रतिबंधित व्यापार गतिविधियों सम्बन्धी अधिनियम, औद्योगिक विकास एवं पंजीकरण अधिनियम इत्यादि देश के सभी कानूनों को नर्म बनाया गया ताकि उनके लिये द्वार खोले जा सकें। विदेशी एक्विटी स्वयंमेव बढ़ कर 40 से 51 प्रतिशत हो जाएगी जिसके लिये न सरकार की अनुमति और न ही शेयर धारकों की सहमति लेने की आवश्यकता होगी। अब 100 प्रतिशत विदेशी शेयरों वाली कम्पनी की स्थापना भी सम्भव हैं। उसे सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा सकती हैं। यहां तक कि वे लाभ एवं देश प्रत्यावर्तन को दूसरे देशों में परिवर्तित कर सकती हैं। इसके लिये कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र को दी गई राष्ट्रीय प्राथमिकता बदली जा रही है। ज्ञातव्य है कि इसी क्षेत्र के फलस्वरूप हमारा अर्थतंत्र प्रगति के शिखर पर पहुंच सका है। अब इसी सार्वजनिक क्षेत्र को शत्रु नंबर एक माना जा रहा है। उसे तीव्र गति से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा हैं। विश्व बैंक ने जो निदान सुझाया है उसके अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कुल 244 कम्पनियों में से 82 कम्पनियों को बंद कर दिया जाए। 92 की पहचान बीमान कम्पनियों के रूप में की गई है। उनमें से 58 कम्पनियां गम्भीर रूप से बीमार हैं। इन संस्थानों में काम करने वाले 8 लाख श्रमिकों के सिर पर रोजगार-समाप्ति की तलवार लटक रही है। इन कम्पनियों को बंद कर देने और श्रमिकों को 'निकास' की प्रक्रिया सरल बनाने और इसके लिये राष्ट्रीय नवीकरण कोष का हथकण्डा प्रयोग में लाने को कहा गया है। समस्या का यही समाधान सुझाया गया है। इस खतरे को अनुभव करते हुए देश के मजदूर वर्ग ने इसका विभिन्न ढंगों से प्रतिकार करने का प्रयास किया है। इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में दो बड़ी आम हड़तालें की गई तथा भारत बंद का आयोजन किया गया है। पहली हड़ताल .....और दूसरी हड़ताल तथा भारत बंद 9 सितम्बर, 1993 को आयोजित किया गया था। इसके लिये ट्रेड यूनियनों के अतिरिक्त इन नीतियों का विरोध करने वाले सभी जन संगठनों को लामबंद किया गया था। किन्तु जनता तथा मजदूर वर्ग द्वारा प्रतिकार किये जाने पर भी सरकार विश्व बैंक के निर्णयों को कार्यरूप दे रही है। इसका विवरण महासचिव की रिपोर्ट में दिया गया है। तथापि में कुछ विशेष महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सरकार अर्थतंत्र के मूलभूत क्षेत्र में क्या कर रही है। आईये, हम इसका मूल्यांकन करें। संसाधनों की कमी के नाम पर सरकार ने पहले ही देश के तेल भण्डार जिनका ओ एन जी सी ने पता लगाया था और विकसित किया था, विदेशी बहुराष्ट्रीयों को सौंप दिये हैं। ओ एन जी सी लगभग 5 या 6 डालर प्रति बैरल लागत पर तेल निकालता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय लागत 16 से 18 डालर प्रति बैरल है। यह वही मूल्य है जिसकी पेशकश सरकार निजी निवेशकों और वह भी विदेशी मुद्रा में को कर रही है। उनके द्वारा ओ एन जी सी द्वारा विकसित ढांचे का प्रयोग करके और उसके ही मूल्य पर तेल कर उत्पादन किया जाएगा।

हाल ही में ओ एन जी सी के अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने एक दिन की हड़ताल की थी। वे ओ एन जी सी के प्रति भेदभाव करने वाली भारत सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने सरकार से पूछा है कि वह देशी तथा विदेशी निजी कम्पनियों को 18 डालर प्रति बैरल के मूल्य का भुगतान क्यों कर रही है जबकि उनकी तुलना में ओ एन जी सी को बड़ी तुच्छ राशि दी जा रही है। उनका कहना है कि यदि जिन मूल्य दरों की पेशकश देशी तथा विदेशी निजी कम्पनियों को दी गई है, ओ एन जी सी को दिये जाएं तो उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी और वे दो-तीन गुणा अधिक उत्पादन कर सकेगी। किन्तु सरकार तो उसे एक कम्पनी के रूप में परिवर्तित करने पर तुली हुई है और वह उसके शेयर विदेशी निवेशकों को बेच रही है।

भारत सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित की गई सबसे बड़ी कम्पनी के माध्यम से न्यूनतम लागत पर तेल का उत्पादन करता है और वह सरकार को नाम मात्र के मूल्यों पर जैसा कि ऊपर बताया गया है, तेल की आपूर्ति करती है। नयी नीति के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम मूल्यों में 2-3 गुणा वृद्धि हो जाएगी और इसका अनेक क्षेत्रों में उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इनके मूल्यों में स्वयंमेव वृद्धि हो जाएगी तथा बटे हुए मूल्यों वाला हमारा अर्थतंत्र बाजार में अपने उत्पादों के लिये प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेगा तथा उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। हमारी विदेशी मुद्रा की देनदारियों में अपार वृद्धि हो जाएगी। ओ एन जी सी के अन्तर्गत हमने जिन सुविधाओं को उपलब्ध कराया था, वे व्यर्थ चली जाएंगी। विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। हमारे कुशल श्रमिकों, तकनीकी विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों की योग्यता धरी रह जाएगी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह सब राष्ट्रीय हितों के विरोध में ही जाएगा।

संसाधनों की कमी के नाम पर विद्युत एवं ऊर्जा क्षेत्र के द्वारा विदेशी बहुराष्ट्रीयों के लिये खोले गए हैं। उन्हें भारत सरकार की ओर से सम्प्रभुता की गारंटी देने के साथ-साथ निवेशों पर 16% वापसी की गारंटी भी दी गई है। राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विदेशी बहुराष्ट्रीयों के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं। महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने एक अमरीकी कम्पनी एनट्रान के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अन्तर्गत 2 चरणों में 2015 मैगावट बिजली के उत्पादन हेतु एक परियोजना स्थापित की जाएगी। इस योजना पर वास्तविक निवेश 9053 करोड़ रुपये का होगा। इस परियोजना में प्रति मैगावाट पूंजी निवेश 4.4 करोड़ रुपये होगा जबकि इसके विपरीत आठवीं पंच वर्षीय योजना में 1.6 से 2 करोड़ रुपये प्रति मैगावाट निवेश करने का विचार किया गया था। महाराष्ट्र बिजली बोर्ड पहले चरण से 2.93 रुपये प्रति यूनिट तथा दूसरे चरण के लिये 2.44 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने को सहमत हो गया है। वितरण तथा संप्रेषण की लागत को शामिल करने पर यह 4.00 रुपये से कम नहीं बैठेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के उपभोक्ता प्रति यूनिट के लिये 1/- रुपये का भुगतान करते हैं। जब नयी बहुराष्ट्रीय परियोजना का उत्पादन शुरू तो इसमें असाधारण वृद्धि हो जाएगी। इसलिये बिजली की दरों में न्यूनतम दोगुणा वृद्धि होने जा रही है। यह उदाहरण मोटे तौर पर नयी नीतियों की दिशा की ओर संकेत करता है जिन्हें इस समय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरूप दिया जा रहा है। एक और तथ्य को अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिये। बी एच ई एल में स्थापित हमारी आंतरिक संचना से 1/3 लागत

पर ही बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। किन्तु उसे विखण्डित किया जा रहा है। विशालकाय कम्पनी बी एच ई एल जिससे अधिकारियों सहित 48000 कर्मचारी काम करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत मशीनों का उत्पादन कर सकती है और वह विश्व बाजार में प्रभावशाली ढंग से प्रतियोगिता करने की स्थिति में हैं। इसी कम्पनी को अब कार्यादेशों की भयानक कमी का सामना करना पड़ रहा है जबकि इसके विपरीत विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बड़ी गर्मजोशी से 'स्वागतम' कहा जा रहा है। इसका एक अद्‌भुत पहलू भी है। पूंजीवादी अर्थतंत्र में हानि उठाने का खतरा सदा बना रहता है किन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मामला ही भिन्न है। उन्हें तो बस लाभ और लाभ ही होगा।.......इसी से पता चल जाता है कि मनमोहन अर्थतंत्र कैसे काम करता है। हानि का राष्ट्रीयकरण और लाभ का निजीकरण।

नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन भी एक ऐसी ही कम्पनी है। वह सफलतापूर्वक विद्युत उत्पादन कर रही है। किन्तु अब उसे भी बी एच ई एल जैसी नीयति का सामना करना पड़ेगा। विदेशी बहुराष्ट्रीयों के साथ प्राथमिकता वाला सद्‌व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादक इकाईयों पर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं होगा।

जिन्हें अपने-अपने देशों में जबरदस्त मंदे का सामना करना पड़ रहा है वे अपने उत्पादों की बाढ़ भारतीय बाजार में ले आएंगे जो इस समय उनके कारोबार को बढ़ाने के लिये उपलब्ध है। बिजली के ऊंचे मूल्यों से उद्योग कृषि क्षेत्र पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। कोयला के मूल्यों में भी उछाला लाया जा रहा है। ऊंचे मूल्यों वाले तेल, ऊर्जा, कोयला इत्यादि मिल कर कहर बरपा देंगे और अ-उद्योगीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो पहले ही जारी हो चुकी है।

हमारा अखबारी कागज़ बनाने का उद्योग जो हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन की केरल शाखा की भांति अपनी गुणवत्ता, उत्पादकता और लाभदायकता में श्रेष्ठ है को भी उदारीकृत आयात नीति के कारण काम बंदी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की अनेक इकाईयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और फास्फेटिक उर्वरक की इकाईयों के सिर पर गम्भीर खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति तभी से उत्पन्न हुई है जबसे सब्सिडी में कटौती की गई है और उर्वरक आयात का उदारीकरण किया गया हैं। फास्फेटिक उर्वरक डी ए पी भारत के बाजार में निर्माता कम्पनी की अपनी लागत से भी कम मूल्य पर अर्थात 160 से 170 डालर प्रति टन की दर से लाई जा रही है जबकि इसी उर्वरक की घरेलू लागत उसके अपने देश (अमरीका) में लगभग 265 डालर प्रति टन आती है। फास्फेटिक उर्वरक बनाने वाली सभी 14 इकाईयां संकटपूर्ण स्थिति में हैं। उनके बंद होने के खतरा विद्यमान है। जब तक आयात नीति में परिवर्तन नहीं किया जाता और विदेशी उर्वरक की बाढ़ को रोका नहीं जाएगा, ऐसी स्थिति बनी रहेगी।

नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। यह उर्वरक भारत की धरती को भयानक हानि पहुंचा रही है

और इसके प्रयोग से उसका पुष्टिकारक तत्व क्षीण हो जाएगा ।

जयपुर में आयोजित विज्ञान कांग्रेस ने भी ऐसे ही विचारों को रेखांकित किया था । यह कांग्रेस जनवरी में हुई थी । उर्वरक उद्योग की यूनियनों ने भी अपने ज्ञापन में प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया है । उन्होंने विकसित पूंजीवादी देशों में विद्यमान सब्सिडी दरों की तुलना हमारे अपने देश में दी जा रही सब्सिडी से की है । यह इस प्रकार है :

प्रति हेक्टर सब्सिडी - अमरीकी डालर में

भारत	अमरीका	युरोपीय समुदाय	जापान
4.3	148.5	238.4	259.1

इसलिये कृषि सब्सिडी के मामले में विश्व बैंक की शर्तों को मानने का अर्थ हमारे अपने कृषि उत्पादन को नष्ट करने के उनके (साम्राज्यवादियों) प्रयासों को सफल बनाना होगा । संक्षेप में, इन नीतियों का कुल प्रभाव यह होगा कि भारत विश्व बाजार में कृषि उत्पादों के लिये जिसमें अनाज भी शामिल हैं, प्रतियोगिता-स्थली बन जाएगा, कृषि क्षेत्र अवन्नति की ओर अग्रसर होगा, हमारा उत्पादन कम हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप हम खुकाक सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिये आयात पर निर्भर करने लगेंगे ।

भारत में पूंजीगत-माल के उत्पादन को अनेक ढंगों से अपंग बना दिया जाएगा । हमारे अधिकांश पूंजीगत-माल तथा माध्यमिक माल का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में होता है । आज हमारी सार्वजनिक इकाईयों विद्युत गृहों, तेल शोध कारखानों तथा उर्वरक संयंत्रों इत्यादि का निर्माण कर सकती हैं या दूसरे शब्दों में वे 'विचार को मूर्त रूप' देने में हैं । हमारे देश में एक ओर तो सरकार की विशेष सहमति से विदेशी बहुराष्ट्रीयों का मुक्त प्रवेश हो रह संयुक्त उद्यमों या किसी के सहयोग से विदेशी पूंजीनिवेश के लिये उन्म प्रयास किये जा रहे है ज सार्वजनिक क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में नकारात्मक दृष्टिकोण अपन प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने की कार्रवाई चल रही है । पूंजीगत-माल का आयात उत्पादन में जबरदस्त कमी आ रही है । पूंजीगत-माल सम्बन्धी उद्योग के उत्पादन में कमी के तक 8.6% थे और मिलने वाली सबसे अंतिम रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े 12% को पार

पूंजीगत-माल का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योगपती जो अभी तक वैश्वीकरण अंततः यह पता चल ही गया है कि विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों की तुलना में उनके

रहा है । उन्होंने सरकार से 'समान व्यवहार' करने की मांग की है । उन्होंने यह भी बताया है कि उत्तम पूंजीगत-माल पर शुल्क में दी जाने वाली छूटों से भारतीय निर्माताओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है । वे अब विदेशी पूंजी के आधिपत्य के दुष्प्रभावों को भी अनुभव करने लगे हैं और सरकार से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति अपने रुख में परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं ।

उनके विचारों को स्पष्ट करने के उद्देश्य से मैं बिजनस टुडे के अक्तूबर 7.12.93 के एक लेख को उद्धरित करना चाहूंगा । थापर समूह के अध्यक्ष श्री ललित मोहन थापर स्वीकार करते हैं "मुझे भय है कि हममें से अधिकांश लोगो ने जिन्होंने शुरू में उदारीकरण का समर्थन किया था, इसके वास्तविक अर्थों को समझा ही नहीं है ।" विदेशी पूंजीपति कहने लगे हैं कि संयुक्त उद्यमों में उनकी अब और दिलचस्पी नहीं रही । अधिकांश विदेशी पूंजीनिवेश और इक्विटी शेयरों की मांग करने लगे हैं । वे चाहते हैं कि प्रबंधन का निमंत्रण भी उनके पास हो । यदि वे संयुक्त उद्यमों में बने रहते हैं तो उस स्थिति में अधिकांश भारतीय व्यवसायी समझते हैं कि उनके आगे अपने विदेशी सहयोगी का कनिष्ठ सहयोगी बनने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रहता ।

प्रौद्योगिकी एक है । विदेशी पूंजीनिवेशक अपनी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पैसे लेकर भी हमें देने को तैयार नहीं हैं । अधिकांश मामलों में वे उस पर अपना स्वामित्व चाहते हैं । इसका अर्थ है अधिकांश उद्यमों पर उनका नियंत्रण ।

अनेक विदेशी कम्पनियां चाहेंगी कि वे स्थानीय रूप से अपने उत्पाद तैयार न करें । वे उनका आयात करना चाहेंगी । इससे एक भिन्न प्रकार का खतरा उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि संयुक्त उद्यम विपणन एवं वितरण के लिये ही स्थापित किये गए हैं, सामान तैयार करने के लिये नहीं । ब्रांड निर्माण जैसे मुद्दों में तो बहुराष्ट्रीयों का खतरा और भी बढ़ जाता है । विदेशी कम्पनियां शोध एवं विकास कार्यों में भी कोई रूची नहीं दिखा रहीं । रुपये का अवमूल्यन होने से विदेशी ...ों को अच्छी स्थिति में चल रहीं भारतीय कम्पनियों को हस्तगत करने में सहायता मिली है । 'बम्बई समूह' के ...ने इस सम्बन्ध में जो चेतावनी दी है, उससे आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है । उसके अनुसार ... विदेशी कम्पनियों के फंदे में फंस चुका है । उन्हें अपने घर में भी खतरे का सामना करना पड़ रहा है ।

...यार करने वाला उद्योग को समाप्त किया जा रहा है । जो हमारे औद्योगिक विकास का प्रमुख ...वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ।

...कताओं की सूची में दूरसंचार तथा वित्तीय क्षेत्र भी शामिल हैं । भारत सरकार उन्हें सभी ...ारा दूरसंचार उद्योग आज 70 लाख दूरभाषों (टेलीफोन) का निर्माण कर चुका है । यह ...ा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है । इस उद्योग की विकास दर 17 प्रतिशत प्रति वर्ष

है जिसे 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय दृष्टि से भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसके द्वारा बनाए गए स्विच सर्कट सफल रहे हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (III), हिन्दुस्तान केबल्स, हिन्दुस्तान टेलीफोनस इत्यादि उत्पादक इकाईयां बढ़ रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से ही स्थापित की गई थीं। अब सभी कार्यादेश निजी क्षेत्र को दिये जा रहे हैं जिससे इस क्षेत्र के वित्तीय हितों को क्षति पहुंची है। महानगर टेलीफोन निगम ने पहले ही निजी हितों को अपने 31 शेयरों की पुंजी विनिवेश कर दिया है और अब इस उद्योग को दूरसंचार विभाग से ही छीनने के प्रयास किये जा रहे हैं। और निजीकरण की दिशा में प्रारम्भिक कदम के रूप में 3-4 निगम बनाए जाएंगे। विदेशी बहुराष्ट्रीयों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस क्षेत्र को हड़पने के उद्देश्य से एट एण्ड टी जैसी दूरसंचार उद्योग की इजारेदार कम्पनी भारत आ रही है।

समूचे तौर पर दूरसंचार का यह संवेदनशील क्षेत्र जिसका संबंध देश की रक्षा सम्बन्धी मामलों से है को भी विदेशी बहुराष्ट्रीयों के हवाले किया जा रहा है। इससे इसके मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाएगी, उपभोक्ताओं पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा और यह विशाल ग्रामीण क्षेत्र की वित्तीय क्षमता की परिधि से बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही कई हज़ार कर्मचारियों को रोजगार की क्षति झेलनी पड़ेगी।

कार्य कुशलता और लाभदायकता बढ़ाने के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अनेक अंकुश लगाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र को विदेशी तथा भारतीय निजी क्षेत्र के लिये खुला छोड़ा जा रहा है। विदेशी बैंकों द्वारा 'जमानत घोटाले' में जो भूमिका निभाई गई है, उससे भी उनके आगे बढ़ने पर कोई रोक नहीं लग सकी है।

भारत में बैंकिंग उद्योग के विकास से जनता में उसके प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हुई थी, निवेशक उसमें निवेश किये गए धन को सुरक्षित मानते थे जबकि निजी क्षेत्र निवेशक के मूल्य पर समय-समय पर संकटग्रस्त होता रहा है। अब पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने, गरीब वर्गों को सहायता पहुंचाने और विकास के लिये संसाधन जुटाने जैसे सामाजिक उद्देश्य समाप्त हो गए हैं। विदेशी बैंकों को इस उद्योग में छा जाने की अनुमति दी गई है। बैंको का ग्रामीण नेटवर्क बंद किया जा रहा है। इसके लिये बैंकिंग के नियमों तक में भी संशोधन किया जा रहा है।

बीमा क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसने सदा हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति की है। इस क्षेत्र द्वारा जुटाए गए भारी धन को विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं और देश के विकास की दूसरी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। निवेशों की वापसी, परिसम्पत्तियां, जीवन कोष, आरक्षित कोष, लाभ तथा अन्य वित्तीय सम्पत्तियां निःसंदेह जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता की ओर संकेत करती हैं। जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों की एक्विटी में वृद्धि करने का कोई कारण ही नहीं है। देश के बीमा उद्योग का साधारण प्रीमियम विश्व भर में सबसे कम है। शायद यही उसे निजी हाथों में सौंपने का एकमात्र कारण दिखाई देता है।

मैं अन्य क्षेत्रों के ब्योरे में जाना नहीं चाहता। उद्योगों में बीमारी बढ़ रही है। विशेष रूप से लघु उद्योग एवं कपड़ा, पटसन, काअर इत्यादि हमारे परम्परागत उद्योग इस व्याधि से पीड़ित हैं। यहां लाखों लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। दूसरे क्षेत्रों में श्रमिकों के रोजगार को नया खतरा उत्पन्न हो गया है और इसके साथ ही बेरोजगारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

अ- उद्योगीकरण की प्रक्रिया जारी है और नयी नीतियों को कार्यरूप दिया जा रहा है। विदेशी निगमों का सौल्लासपूर्ण स्वागत किया जा रहा है। कई मामलों में तो उन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है। इस पर भी विदेशी कम्पनियां अपनी नवीनतम प्रौद्योगिकी हमें देने को तैयार नहीं है। वे लगातार शेयरों पर अपना नियंत्रण करने और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से उन पर नियंत्रण करने के लिये हठ कर रही हैं। देश के भीतरी उत्पादन प्रक्रिया में उनकी कोई रुचि नहीं है। शोध एवं विकास कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं है। फिर भी उन्हें अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। हमने पिछले वर्षों में अथक परिश्रम करके जो कुछ भी बनाया है, उसे नष्ट करने के लिये गम्भीर प्रयास किये जा रहे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में ऐसी खतरनाक स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी।

ट्रेड यूनियनों के प्रत्युत्तर की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं।

इन नीतियों के विरोध में राष्ट्रीय हड़ताल कार्यक्रम के अतिरिक्त उद्योगवार हड़तालें आयोजित की जा चुकी हैं। इस संकट ने कई मामलों में श्रमिकों और अधिकारियों को अपना रोजगार एवं उद्योग बचाने के लिये संयुक्त कार्रवाईयां करने पर विवश कर दिया है। राजनीतिक एवं सांगठनिक मतभेद होने पर भी ट्रेड यूनियनों में एकता का रुझान बढ़ रहा है। अधिकारियों के संगठनों में भी संयुक्त कार्रवाईयां करने का रुझान बना है। मैं यहां इस बात का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता कि मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों को समाप्त करने के लिये प्रयास जारी हैं। कुछ दुर्बल प्रकृति की ट्रेड यूनियनें संयुक्त संघर्षों में भाग नहीं ले रही हैं। क्योंकि हमले बढ़ रहे हैं, इसलिये इन सभी को बेनकाब करके पराजित करना होगा। सभी ट्रेड यूनियनों एवं जनसंगठनों को अपने संयुक्त संघर्ष चलाने होंगे तथा उनमें दृढता लानी होगी।

इस स्थिति में सी आई टी यू को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। परिसंघ के विचार जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, पर और बल देना चाहिये और इसे साकार रूप देने के लिये विधियां तलाश करनी चाहियें।

हमने उद्योगवार फेडरेशनें बनाने पर बल दिया था। इस काम को गम्भीरता से लेना होगा। एकता का संघर्ष आज भी हमारे लिये सबसे बड़ा काम है क्योंकि मजदूर आंदोलन पर हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसलिये मैं एक बार फिर सभी ट्रेड यूनियनों से अपील करुँगा कि वे एकता के परचम को और ऊंचा उठाएं। वे न केवल अपने हितों पर हो रहे

हमलों का करारा जवाब दें अपितु देश की स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता की रक्षा भी करें ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कुछ परेशान करने वाली बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । ट्रेड यूनियनों को ये बातें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देनी चाहियें ।

केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता एवं उदासीनता के कारण बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने से देश भर में साम्प्रदायिक शक्तियों का दु: साहस बढ़ गया है और राष्ट्रीय एकता का ताना-बाना ही खतरे में पड़ गया है । आज वे लोग समस्याओं का समाधान निकालने के लिये सही कदम नहीं उठा रहे हैं । जातिवाद भी अपना सिर उठा रहा है । इससे जनता विशेष रूप से मजदूर वर्ग की एकता संकट में पड़ गई है ।

बिल क्लिंटन प्रशासन द्वारा पाकिस्तान के तर्कों का समर्थन करने और हमारे अपने देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किये जाने पर भारत सरकार ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला है ।

ट्रेड यूनियनों को भारत सरकार के इस दुर्बल रुख का कड़ा नोटिस लेते हुए हमारे देश के आंतरिक मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप के विरोध में संयुक्त रूप से प्रतिकार करना चाहिये ।

मुझे अनुमति प्रदान करें कि मैं आपकी ओर से बिहार सी आई टी यू का धन्यवाद करने की जिसने ऐतिहासिक शहर पटना में हमारे सम्मेलन के सफल आयोजन के लिये शानदार प्रबंध किये हैं । इन्हीं शब्दों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

महासचिव की रिपोर्ट

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

हम कलकत्ता में 13-17 फरवरी, 1991 को आयोजित सातवें सम्मेलन के तीन वर्ष पश्चात् यहां एकत्रित हुए हैं। इसी मध्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिनका हमारे आंदोलन और भावी कार्य नीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। अत: सी आई टी यू के आठवें सम्मेलन के समक्ष ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का अम्बार लगा है जिन्हें हमने अपने वाले दिनों में पूर्ण करना है।

श्रद्धांजलि

2. सर्वप्रथम हम अपने उन अनेक उत्कृष्ट नेताओं को श्रद्धांजलि भेंट करेंगे जो पिछले सम्मेलन के पश्चात् से हमें विच्छोह दे गए हैं। सी आई टी यू के उपाध्यक्ष कामरेड मनोरंजन राय जिन्होंने अपना अंतिम सांस 13 जून, 1992 को लिया, भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अत्यंत विशिष्ट नेताओं में से एक थे। उनके चले जाने से हमने अपना एक महान स्तम्भ खो दिया है। वह जीवन के अंतिम क्षणों तक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहे। सी आई टी यू के एक अन्य उपाध्यक्ष कामरेड कमल सरकार जो ट्रेड यूनियन आंदोलन के पुरोधा थे का 9 जून, 1992 को देहांत हो गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के श्रमिक-आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। उन्होंने पश्चिम बंगाल तथा उससे बाहर अन्य राज्यों में सी आई टी यू को सुदृढ़ करने के काम में अपूर्व योगदान दिया।

3. हमने कार्य समिति के दो सदस्यों कामरेड जैमिनी साहा (पश्चिम बंगाल) तथा कामरेड ओ जे जोसेफ (केरल), जनरल कौंसिल के पांच सदस्यों कामरेड ए डी शास्त्री (महाराष्ट्र), कामरेड के जार्ज (आंध्र प्रदेश), कामरेड स्वप्न बोस (पश्चिम बंगाल), कामरेड भाग सिंह सज्जन (पंजाब) और कामरेड मोतीलाल शर्मा को खो दिया है। सी आई टी यू की त्रिपुरा राज्य समिति के पूर्व महासचिव कामरेड बीरेन दत्ता, जो कार्य समिति के सदस्य भी थे, अखिल भारतीय कोयला मजदूर फेडरेशन के सचिव कामरेड जे के बोस, सी आई टी यू की महाराष्ट्र राज्य समिति के उपाध्यक्ष डाक्टर ए बी सावंत और सी आई टी यू की उड़ीसा राज्य समिति के उपाध्यक्ष आनंदन नाम्बियार जो रेलवे कर्मचारियों के उल्लेखनीय नेता, हमारी कार्य समिति के पूर्व सदस्य, एवं योग्य संसद विद् थे, भी हमारे मध्य नहीं रहे हैं।

4. क्रांतिकारी आंदोलन के अनेक महत्वपूर्ण पुरोधाओं जिनमें कामरेड एम. बासवपुनैया सदस्य पोलिट ब्यूरो, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), कामरेड अचिंत्य भट्टाचार्य तथा कामरेड सतवंत सिंह दोनों केन्द्रीय समिति सदस्य सी पी

आई (एम) एवं कामरेड जे चीमा,से भी हमें वंचित होना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तीन प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं कामरेड प्रभास राए, कामरेड गणेश घोष तथा कामरेड सुकुमार सेन गुप्त भी हमें विच्छोह दे गए हैं।

5. अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख पुरोधा कामरेड अब्दुल्ला रसूल, अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ के महासचिव कामरेड पी के कुंजायन, केरल के अग्रणी किसान नेता कामरेड एम के केलू तथा तमिलनाडु में लोकतांत्रिक महिला आंदोलन की प्रमुख पुरोधा कामरेड जानकी अम्मा ने भी इसी अवधि में ही अपना अंतिम सांस लिया।

6. पिछले सम्मेलन के पश्चात् भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अनेक महत्वपूर्ण नेता हमसे बिछुड़ चुके हैं। इनमें उल्लेखनीय हैं स्वतंत्रता सेनानी तथा लम्बी अवधि तक एटक के महासचिव रहे कामरेड एस ए डांगे, एटक के सचिव कामरेड टी एन. सिद्धान्त, एटक के उपाध्यक्ष कामरेड बालचन्द्र त्रिवेदीएच एम एस के उपाध्यक्ष कामरेड समरेन्द्र कुंडू, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव कामरेड के एम मैथ्यू, मोटर परिवहन उद्योग में एच एम एस नेता कामरेड भाउ पाटक तथा ए आई आर एफ के नेता कामरेड पारितोष बैनर्जी भी हमारे मध्य नहीं रहे हैं। इंटक के उपाध्यक्ष श्री वी जी बोपाल जो इंटक के पूर्व अध्यक्ष भी रहे भी विच्छोह दे गए हैं।

7. इसी अवधि में पूर्व प्रधानमंत्री तथा कांग्रेस-इ अध्यक्ष श्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को लिट्टे उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा सी पी आई नेता कामरेड विश्वनाथ मुखर्जी, प्रख्यात फिल्म निदेशक श्री सत्यजीत रे एवं उत्पल दत्त, आई एन ए के नायक कर्नल पी के सहगल का इसी अवधि में देहांत हुआ। हम इन नेताओं के देहावसान पर अपने गहरे शोक की अभिव्यक्ति करते हैं।

8. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीकी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा ए एन सी नेता कामरेड क्रिस हानी की दक्षिणपंथी उग्रवादियों ने जघन्य हत्या कर दी, इस घटना की विश्व भर में निंदा की गई। सुप्रसिद्ध ए एन सी नेता ओलिवर रम्बो का दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित सफल समझौते के सम्पन्न होने से पूर्व देहांत हो गया। ट्रेड यूनियनों की विश्व फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड इब्राहिम जकारिया जिन्होंने कई दशकों तक डब्ल्यू एफ टी यू में उल्लेखनीय भूमिका निभाई भी एवं सोवियन राजनेता और सोवियत संघ के पूर्व विदेश मंत्री कामरेड आंद्रेई ग्रोमिको का इसी अवधि देहावसान हुआ। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यू एम एल) के दो प्रमुख नेताओं कामरेड मदन भंडारी तथा कामरेड जिवा राज आश्रित 16 मई, 1993 को एक रहस्यमयी कार दुर्घटना में मारे गए।

हम इन वीर नेताओं एवं शहीदों को जिन्होंने पिछले तीन वर्षों की अवधि में मजदूर वर्ग के आंदोलन में सक्रिय रहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनमें उल्लेखनीय डाला सीमेंट के शहीद हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस समय गोलियों से भून डाला जब वे सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त सीमेंट संयंत्र के निजीकरण का विरोध कर

रहे थे। पश्चिम बंगाल में बनारहाट चाय बागान के 17 श्रमिकों की 15 जून 1993 को इंटक के गुण्डों ने हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के भिलाई नगर में 1 जुलाई, 1992 को भाजपा सरकार की पुलिस ने लगभग 20 श्रमिकों की गोलियां मार कर हत्या कर दी। आंध्र प्रदेश में नेलीमारला के पांच श्रमिकों को उस समय पुलिस की गोलीबारी में अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा जब वे तालाबंदी समाप्त करने की मांग कर रहे थे। हरियाणा में अधिक वेतन के लिये संघर्ष करते समय दो प्रमुख भट्ठा मजदूर पुलिस की गोली का शिकार हो गए। पंजाब, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा केरल के अनेक कामरेड मजदूर एवं किसान संघर्षों में भाग लेते हुए मारे जा चुके हैं। हम इन सभी शहीदों को सादर श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।

9. हम उन हजारों निर्दोष लोगों का भी सादर स्मरण करेंगे जो महाराष्ट्र के लातूर जिले के किल्लारी नगर में आए भयानक भूकम्प के कारण भोर के समय अपनी आंखें भी खोल नहीं सके। निःसंदेह हमारे देश की यह सर्वाधिक बड़ी त्रासदी थी। 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पश्चात् साम्प्रदायिकता के वीभत्स में अनेक निर्दोष लोग साम्प्रदायिक गुण्डों की विनाश लीला का शिकार हुए। इन हत्याओं के कारण पूरे विश्व के आगे हमारा सिर मारे लज्जा के झुक गया है। हमारे देश की धरती पर साम्प्रदायिक-संहार का शिकार हुए इन लोगों को भी हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

10. अपने बिछुड़े नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट करते समय हम उनके अधूरे कार्यों को पूरी दृढ़ता के साथ पूर्ण करने एवं अपने महान लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में संघर्ष करते रहने का प्रण करते हैं।

बदलता अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

11. हमारे पिछले सम्मेलन के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में समाज़वाद का विखण्डन होने के दुष्परिणाम स्वरूप विश्व स्तर पर शक्तियों का संतुलन ही बदल गया हैं। विश्व भर में श्रमिकों को इन घटनाओं से सदमा पहुंचा है। उन्हें आश्चर्य है कि सभी के लिये रोजगार उपलब्ध कराने, मुफ्त चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं, आवास, पेंशन और सवैतिक वार्षिक अवकाश उपलब्ध कराने पर भी श्रमिक वर्ग समाजवाद की रक्षा करने में विफल क्यों रहा है।

12. पूंजीवादी राज्य के प्रचारक कहते हैं कि समाजवाद व्यवस्था की विफलता के कारण ही ऐसा हुआ है और इसलिये समाजवाद तीव्र प्रगति नहीं कर सकता। इसलिये वे वकालत करते हैं कि पूंजीवाद ही मानव सभ्यता का अंतिम चरण है और वे विश्व भर में श्रमिक वर्ग को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अत: अत: श्रमिकों के लिए इस बात को समझना आवश्यक है कि अपने लम्बे समय के अस्तित्व के पश्चात् समाजवादी व्यवस्था का पराभव क्यों हुआ ?

13. हमें एक बात गांठ बांध लेनी चाहिये कि यह समाजवाद भी विफलता नहीं थी अपितु समाजवाद के निर्माण में रही विसंगतियों के कारण ऐसी स्थति उत्पन्न हुई । समाजवादी व्यवस्था तब तक प्रगति नहीं कर सकती जब तक समाजवादी मूल्यों के लिये संघर्ष करने हेतु श्रमिक विचारधारा की दृष्टि से श्रमिक वर्ग को तैयार नहीं किया जाता और उच्च आर्थिक विकास हेतु जनता के जीवन स्तर में निरंतर सुधार नहीं किया जाता । समाजवाद की प्रगति के लिये उपभोक्ता वस्तु उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जीवन स्तर में नरंतर सुधार को सुनिश्चित बनाने के लिये उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि में श्रमिकों की अधिक प्रभावी भागीदारी जैसी बातों की समाजवाद के निर्माण के अंतिम चरण में दृष्टिलोप कर दिया गया था । समाजवादी जागरूकता के अभाव ने श्रमिक वर्ग को समाजवाद की प्रगति के संघर्ष में निशस्त्र कर दिया था । इस पर भी कि समाजवाद के निर्माण के प्रारम्भिक चरण में शानदार प्रगति की गई थी ।

14. लोकतंत्र के बिना समाजवाद प्रगति नहीं कर सकता । अनेक वर्षों से राज्य की प्रशासनिक संरचना, कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनें नौकरशाही का शिकार हो चुकी थीं । इन मंचों पर मजदूर वर्ग के स्वर की प्रतिध्वनि सुनाई देनी बंद हो गई और वे जनता से दूर होने लगे । अत: जिन लोगों के कंधों पर समाजवाद का निर्माण करने का दायित्व डाला ग़या था वे स्वयं ही उस व्यवस्था से विमुख हो गए । सामाजिक ताना-बाना दिन-प्रतिदिन छिन्न-भिन्न होने लगा और जनता में अपने जीवन स्तर को लेकर असंतोष बढ़ने लगा । साम्राज्यवादियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया । अंतिम क्षणों में समाजवाद को बचाने के प्रयास किये गए तथापि मजदूर वर्ग अपनी भीतर शिथिलता के कारण समाजवाद के शत्रुओं के विरोध में संघर्ष नहीं कर सका अंतत: इसका दुष्परिणाम समाजवाद के विखण्डन के रूप में हुआ । श्रमिक वर्ग ने समाजवाद के निर्माण में अग्रिम पंक्ति की अपनी भूमिका की स्थिति कैसे खो दी । हमारे लिये इसका और अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है । इससे हम विश्व में समाजवाद की भावी घटनाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे तथा समुचित सबक ग्रहण करेंगे ।

15. तथापि मजदूर वर्ग ने शनै-शनै स्थिति की गम्भीरता को अनुभव करना शुरू कर दिया है जबकि समाजवाद के अन्तर्गत प्रदत्त उनके अधिकारों को एक-एक करके छीना जा रहा है । मुद्रा प्रसार आकाश छूने लगा है और लोगों का जीवन स्तर बिगड़ता चला जा रहा है । बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ निजीकरण, भारी लाभ और मूल्यों में निरंतर वृद्धि है । भारी स्तर पर कल-कारखानों का बंद होना और बढ़ रही बेरोजगारी आज सामान्य बात बन चुकी है । इस की स्वाभाविक परिणिति सभी पूर्व समाजवादी देशों की जनता में खराब जीवन-परिस्थितियों के बढ़ रहे प्रतिकार के रूप में हुई है । लाल झंडे उठा कर ट्रेड यूनियनें मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिये आगे आने लगी हैं । हड़तालें तथा प्रदर्शन नित्य प्रतिदिन की घटनाएं बन चुकी हैं । पुलिस की दमनात्मक कार्रवाईयां की इसे रोक नहीं पा रही । इन सभी देशों में मई दिवस के अवसर पर जनसभाएं की गई । अमर पक्षी की भांति समाजवाद की भावना एक बार फिर उड़ान भरेगी, इसमें संदेह नहीं ।

16. जहां एक ओर पूंजीवाद के धर्मगुरू अपनी व्यवस्था का यशगान कर रहें हैं वहीं दूसरी ओर पूंजीवादी देशों की आंतरिक स्थिति बड़ी ही निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। बेरोजगारी असाधारण सीमा तक बढ़ चुकी है। औद्योगिक उत्पादन निश्चलता की स्थिति में है या मंदे का रुझान दिखा रहा है।

17. आर्थिक सहयोग एवं विकास (ओ ई सी डी) संगठन के 24 सदस्य देशों में 360 लाख लोग रोजगार विहीन है। अकेले यूरोपीय भाईचारे के देशों में वर्तमान में बेरोजगारी का आंकड़ा 200 लाख है। ओ ई सी डी के जनरल सैक्रेटेरिएट के एक अनुमान के अनुसार इसमें निकट भविष्य में और वृद्धि होने की आशंका है। यही नहीं शोधार्थियों जिन्होंने युरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार के सम्बन्ध में वर्ष 1993 के दौरान 2.5 प्रतिशत विकास की भविष्यवाणी की थी, वह भी पूरी नहीं हुई है। प्राप्त संकेतों के अनुसार उसमें 0.5 प्रतिशत की कमी होने की सम्भावना है।

18. यूरोपीय मौद्रिक व्यवस्था में कई दरारें आ चुकी हैं। वह सामान्य रूप से चलने में असमर्थ है। व्यवस्था में तनाव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि ग्रेट ब्रिटेन तथा इटली ने विनिमय दर को जस का तस रख छोड़ा है जबकि स्पेन तथा पुर्तगाल ने अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर दिया है। अर्थशास्त्री इसे व्यवस्था के अन्तर्गत ही विभिन्न देशों का असमान विकास मानते हैं। हितों का टकराव इस सीमा तक बढ़ चुका है कि फ्रांस के सरकारी प्रवक्ता ने खुले रूप से जर्मन पर अपने सहयोगी (फ्रांस) के साथ स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस सारे घटना क्रम ने प्रस्तावित आर्थिक एवं मौद्रिक संघ जिसके सम्बन्ध में मास्ट्रिक संधि में सहमति हुई थी, के लिये समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। अधिकांश विकसित पूंजीवादी देशों में ले आफ-तालाबंदियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शानदार प्रगति करने पर भी यह (पूंजीवादी) मरणासन्न व्यवस्था विश्व स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु इसका प्रयोग कर पाने में असमर्थ है। इसके विपरी यह व्यवस्था केवल तृतीय विश्व के देशों के दरिद्रीकरण में वृद्धि करके ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकती है।

19. विश्व बाजार अर्थतंत्र ने पूरे पूंजीवादी विश्व में नव अन्तर्राष्ट्रीय माफिया गिरोहों को बढ़ावा दिया है जिन्हें "सामाजिक दृष्टि से" आर्थिक भागीदार मान लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय दवा उत्पादक-संघ आज सबसे बड़े उपभोक्ता व्यापार का नियंत्रण कर रहा है। यह व्यापार विश्व व्यापी तेल-व्यापार से 2500-3000 खरब डालर या इससे अधिक का है। अधिक खतरनाक बात तो यह है कि दवा उत्पादक संघ शस्त्रास्त्र व्यापार के साथ निकट रूप से जुड़े हुए हैं जो विश्व भर में आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है।

नया विश्व परिदृश्य

20. समाजवाद को धक्का लगना पूंजीवाद के लिये वरदान सिद्ध हुआ है। एक ध्रुवीय विश्व में अमरीकी साम्राज्यवाद

का रुख अधिक आक्रामक हो गया है। वह अब अन्तर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की भूमिका निभाने लगा है। दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में निर्लज्ज हस्तक्षेप करना उसकी दिनचर्या बन चुकी है। इराक में अमरीका की आक्रमक भूमिका सर्वविदित है जहां उसने अपने आक्रमक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग किया था। इराक की आर्थिक नाकाबंदी के फलस्वरूप उसकी जनता आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव में भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गई है। अंगोला और सोमालिया में अमरीकी हस्तक्षेप, क्यूबा की आर्थिक नाकाबंदी के विरोध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का निर्लज्जतापूर्वक उल्लंघन, लातिनी अमरीकी देशों को बार-बार धमकियां देना, युगोस्लाविया में अमरीकी हथकण्डे, रूस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, कश्मीर के प्रश्न पर उसका पाकिस्तान को खुला समर्थन देना, नाभिकीय भयादोहन के माध्यम से उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पैशाचिक हथकण्डे अपनाना, इसके नये एवं जवलंत उदाहरण हैं। अलजीरिया में धार्मिक तत्ववादियों की ओर से बढ़ रहा खतरा हमारे लिये चिंता का कारण बना हुआ है।

21. नव उपनिवेशवाद की साम्राज्यवादी एजेंसियां विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तृतीय विश्व के देशों पर अधिक कड़ी शर्तें थोपने का दु:साहस कर रही हैं।

22. तृतीय विश्व के देशों का शोषण घोटाले के अनुपात तक पहुंच चुका है। तृतीय विश्व के देशों के ऊपर लादे गए ऋण का कुल बोझ 13000 खरब अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। तृतीय विश्व के देशों से विकसित पूंजीवादी देशों को लाभ (मुनाफे) का निर्यात प्रति वर्ष 2000 खरब अमरीका डालर का होना है। यदि इस राशि में ब्याज की देनदारियों को भी शामिल कर लिया जाए तो तृतीय विश्व के देशों की ओर से विकसित पूंजीवादी देशों को उस राशि से अधिक राशि का बहाव होता है जिसे वे ऋण या सहायता के रुप में प्राप्त कर रहे हैं।

23. अमरीकी साम्राज्यवादियों के भयादोहन मेलिंग के हथकण्डे उस समय चरम सीमा तक पहुंच गए जब पूर्व सोवियत संघ के साथ क्रायोजेनिक राकट प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में सौदा करने पर उसके द्वारा भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया। अमरीकी सरकार ने भारत को सुपर 301 तथा स्पेशल 301 का प्रयोग करके कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। उसने भारत पर बीमा उद्योग का निजीकरण करने और बहुराष्ट्रीय निगमों के लिये उसके द्वार खालने के लिये दबाव डाला जा रहा है।

24. साम्राज्यवादियों के डंकल प्रस्ताव को मनवाने के लिये अपने प्रयास तेज कर दिये हैं। इस प्रस्ताव का मुख उद्देश्य तृतीय विश्व के देशों के बाजार पर कब्जा करके तथा उनके औद्योगिक आधार को तहस-नहस करके, उनके शोषण में और वृद्धि करना है। इसलिये ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिये तृतीय विश्व के देशो के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदार पूंजी द्वारा तथाकथित "नयी आर्थिक व्यवस्था" को थोंपे जाने की कार्रवाई को कड़ी पराजय ही जा सके।

कुछ उत्साहवर्धक घटनाएं

साम्राज्यवादी शक्तियों के विश्व व्यापी आक्रमण होने पर भी विश्व के अनेक भागों में लोकतांत्रिक शक्तियों की बढ़त जारी है। दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को सफलता मिली है। वहां रंगभेदी शक्तियों को न केवल पीछे हटना पड़ा है अपितु सिद्धांत रुप में जनता के बहुमत के शासन को रंगभेद किये बिना स्वीकार करने पर विवश होना पड़ा है। यह एक बड़ी घटना है तथापि प्रतिगामी शक्तियों द्वारा किसी भी प्रगति को तारपीडो करने के लिये प्रयास अनवरत जारी हैं। इन पर दृष्टि रखने अत्यंत महत्वपूर्ण है। जापटा (मैक्सीको) के किसानों का नाफ्टा (एन ए एफ टी एं) के विरुद्ध विद्रोह अमरीकी हथकण्डों के विरोध में जन-प्रतिरोध की शानदार उदाहरण है। गुयान में छेदी जगन की जीन, कैनेडा एवं पश्चिम यूरोप के कुछ देशों जिनमें ग्रीस और इटली भी शामिल हैं में अनुदार दलों की पराजय, पूर्वी यूरोप तथा रुस में निजीकरण तथा बाजार अर्थव्यवस्था के विरोध में प्रतिकारक शक्तियों का अभ्युदय वर्तमान विश्व परिदृश्य के उत्साहवर्धक पक्ष हैं। पोलैंड, लिथुआनियां इत्यादि में वाम पक्षीयों को चुनावों में विजय मिली है। केवल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ही प्रगतिशील शक्तियां सुदृढ़ हो सकती हैं।

26. सी आई टी यू के पिछले सम्मेलन के पश्चात् नेपाल तथा बंगला देश में जनता ने वहां की अधिनायकवादी सत्ता के विरोध में साहसिक संघर्ष किया और वह (जनता) लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने में सफल रही है। नेपाल में कम्यूनिस्टों तथा वाम पंथियों ने भारी संख्या में सीटें जीती हैं। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को धक्के लगे हैं और जन इच्छाओं के आधार पर नयी सरकार बनाई जा सकी है। फिलीपीन्स में जनता ने अधिनायकवादी सत्ता की उखाड़ फैंका और वहां चुनाव कराए गए। उस देश में साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन की प्रक्रिया सुदृढ़तर हुई है। श्रीलंका की घटनाएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं और वहां रक्तपात अनवरत जारी है।

27. चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम और क्यूबा में भारी कठिनाईयां होने पर भी समाजवाद के निर्माण में की गई प्रगति हमारे लिये गर्व का विषय है। वे क्रांतिकारी दर्शन पर दृढ़ रहते हुए निरंतर रिकार्ड प्रगति करते जा रहे हैं, इससे हमें विश्व भर में समाजवाद की रक्षार्थ छेड़े गए अपने संघर्ष में भारी सहायता मिली है।

28. भारत और चीन के मध्य विकसित हो रहे मैत्री संबंध और इसके साथ ही सीमा विवाद पर चल रही वार्ता में प्रगति से हमारे देश की उत्तरी सीमा पर तनाव में उल्लेखनीय कमी करने में दोनों देशों को भारी सहायता मिली हैं।

राष्ट्रीय स्थिति

29. सातवें सम्मेलन में चन्द्रशेखर सरकार जो कांग्रेस पार्टी की दया पर सत्ता में बनी हुई थी, की नीतियों पर तीखे हमले किये गए थे। सम्मेलन ने चन्द्रशेखर सरकार जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से निपटने में विफल रही थी, के त्याग

पत्र की मांग को लेकर राष्ट्र व्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया था। इससे पूर्व कि हमारा अभियान गति पकड़ता चन्द्रशेखर सरकार कांग्रेस (इ) द्वारा समर्थन वापस लिये जाने के परिणामस्वरुप धाराशाई हो गई।

30. संसदीय चुनावों के समय धर्मनिपेक्ष विपक्षी दल कोई संयुक्त दृष्टिकोण नहीं अपना सके। इसके परिणामस्वरुप कांग्रेस-इ को सहायता मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने साम्प्रदायिकता का विषैला प्रचार किया और मतदाताओं को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया। चुनाव प्रक्रिया के मध्य राजीव गांधी की हत्या होने से राष्ट्र को आघात पहुंचा किन्तु कांग्रेस (इ) ने चुनावी लाम लेने के लिये उसका लाभ उठाया।

31. कांग्रेस-इ सबसे बड़ी पार्टी के रुप में उभरी किन्तु स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपनी सरकारें बनाई। इससे केवल राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिये खतरा बढ़ा। जनता दल ने बिहार तथा उड़ीसा में सफलता प्राप्त की। त्रिपुरा में कांग्रेस ने आतंकवादी हथकण्डे अपनाए और चुनावों में धांधलियां कीं। पश्चिम बंगाल में चौथी बार वाम मोर्चा सत्ता में आया और दक्षिण में सहानुभूति लहर चलने के कारण केरल में कांग्रेस-इ के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे ने अल्प बहुमत प्राप्त किया।

32. त्रिशंकु संसद होने पर भी कांग्रेस-इ सत्ता में आई और देश में एक नये प्रकार स्थिति बनी।

33. भारतीय अर्थतंत्र उस समय दिवालियेपन के कागार पर था और देश का विदेशी मुद्रा का भण्डार सर्वाधिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। विश्व बैंक तथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उस स्थिति का पूरा लाभ उठा कर ऋण की पेशकश करते समय अपनी शर्तें लादीं और भारत सरकार ने कोष के सभी निदेशों को मानते हुए उसके आगे समर्पण कर दिया। इसी के अनुरुप दो किश्तों में रुपये का 22 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया। 43 टन सोना विदेश भेजा गया जिससे केवल देश में आतंक ही फैला। अर्थतंत्र अनियमित हो गया, एम आर टी पी को समाप्त प्राय: कर दिया गया और लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। बड़े व्यावसायिक गृहों और बहुराष्ट्रीयों को वे सभी सुविधाएं एवं रियायतें दी गई जिससे वे भारतीय अर्थतंत्र पर अपनी जकड़ और मजबूत कर सकें। घाटे की वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के नाम पर सभी विकास कार्यक्रमों को आंशिक रुप से या पूर्ण रुप से समाप्त किया गया, सब्सिडियों को कम किया गया या वापस ले लिया गया या राष्ट्रीय अखंडता को खोखला करके विश्व बैंक तथा कोष की बजट व्यवस्था तक पैठ बना दी गई।

34. पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार ने उद्योगों को करों में रियासतें दीं और सर्वसाधारण पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिये गए। काले धन को राष्ट्रीय विकास कार्यों में लगाने के स्थान पर उसे (काला धन) शेयर बाजार में प्रविष्ट करने की अनुमति की गई। रुपये की परिवर्तनीयता को लागू करने के फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का मूल्य

नीचे आ गया। बड़े व्यवसायी गृहों को अर्थतंत्र के लघु क्षेत्र में प्रविष्ट होने की पूर्ण अनुमति प्रदान की गई।

35. इन नीतियों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण को ही राष्ट्रीय लक्ष्य बना लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को सभी सब्सिडियों से वंचित किया गया और एस आई सी ए में संशोधन करके इन इकाईयों को बी आई एफ आर के सुपुर्द कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अच्छी खासी चल रही इकाइयों के शेयरों की निजी क्षेत्र को पेशकश की गई जिसके कारण उन्हें भीषण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। निजी क्षेत्र को जिसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं को अर्थतंत्र के कुंजीवत क्षेत्र की पेशकश कर दी गई और इस प्रकार आत्मनिर्भर अर्थतंत्र बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को त्याग दिया गया।

36. सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को निर्गम नीति शुरू करने का विश्वास दिलाया गया और उसकी सद्-इच्छा पर ही श्रमिकों को काम से निकाल बाहर करने के मालिकों के अधिकारों को स्वीकार किया गया।

37. भारत सरकार ने आयात उदारीकरण लागू किया और भारतीय अर्थतंत्र के द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पादों के लिये खोल दिय गए। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आयात शुल्कों में और कमी की गई जिसके कारण भारतीय उद्योग को क्षति पहुंची।

38. विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते थे और नये ऋण की प्रत्येक किश्त के साथ नयी शर्तें लादी जाती रहीं। और इस प्रकार नरसिम्हा राव सरकार ने कोष के सभी निदेशों के आगे समर्पण कर दिया।

भारत की अखंडता को खतरा

39. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा केन्द्र में पिछले अढ़ाई वर्षों से अपनाई गई नयी आर्थिक नीतियों का अनुभव सुगमतापूर्वक यह दर्शाता है कि इससे भारत की आत्म निर्भरता और आर्थिक सम्प्रभुता को खतरा उत्पन्न हो गया है।

40. 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन में मंदे का रुझान देखा गया जबकि 1992-93 में केवल 1.4% वृद्धि हुई। वर्ष 1993-94 के मध्य औद्योगिक उत्पादन में अनुमानित वृद्धि 2.4 प्रतिशत तक होने की सम्भावना है। निर्माता (मैन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र निश्चलता की स्थिति दर्शा रहा है और कुछ क्षेत्रों में तो उत्पादन में भारी कमी हुई है। जहां देश में जनसंख्या वृद्धि की दर 2.4% प्रतिवर्ष है वहीं अनेक औद्योगिक वस्तुओं की खपत में कमी हुई है। इससे भारत की जनता के गरीबी के स्तर में वृद्धि होने का संकेत ही मिलता है।

41. जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, उनमें 1991-92 के मध्य डालर की दृष्टि से वास्तव में कमी ही हुई है। वर्ष 1991-92 में हमारा निर्यात 181 खरब डालर का था जो वर्ष 1991-92 में रुपये का अवमूल्यन होने के कारण कम हो कर 179 खरब डालर का रह गया। रुपये का अवमूल्यन होने पर भी हमारे निर्यात ने गति नहीं पकड़ी। अपितु इसके के फलस्वरुप विकसित पूंजीवादी देशों की लूट में असाधारण वृद्धि हुई है। यह भी रेखांकित करना उचित ही होगा कि भारत को निर्यात बढ़ाने के लिये अपने उत्पाद बहुत कम मूल्य पर बेचेने पड़ रहे हैं। अमरीका में भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह किसी भी मूल्य पर अपने उत्पाद बेच रहा है। भारत का व्यापारिक संतुलन जो वर्ष 1990-91 में 10,640 करोड़ रुपये घाटे का था, वर्ष 1991-92 में और कम होकर 3,809 करोड़ रुपये का रह गया। यह घाटा एक बार फिर बढ़ कर 9,572 करोड़ रुपये का हो गया। भारत सरकार अब उस घाटे को पूरा करने के लिये अपने उत्पाद और कम मूल्य पर बेचने का प्रयास कर रही है। यदि हम अधिक उत्पाद नहीं बेचते तो उस स्थिति में देश को कोष से अधिक धन ऋण लेना पड़ेगा। इस प्रकार देश ऐसी भुल भुलईयां में फंस चुका है, जिससे बाहर निकलना कठिन है। हमारे निर्यात का 90 प्रतिशत भाग प्राथमिक उत्पाद हैं और कोष चाहता है कि हम अपने अर्थतंत्र के इस चरित्र को निरंतर बनाए रखें।

42. जहां विकसित पूंजीवादी देशों में भारी मंदा चल रहा है और कुछ शाखाओं में तो उत्पादन में कमी लाई गई है वहीं ये देश बड़ी बेसब्री से बाजार की खोज में लगे हुए हैं। भारत विश्व के दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में जहां 10 करोड़ ठोस मध्य वर्गीय आय समूह हैं, को विकसित पूंजीवादी देशों की उपभोक्ता वस्तुओं के सर्जनशील बाजार ही बना दिया गया है। वे भारत सरकार पर आयात शुल्कों में और कमी करने के लिये दबाव डाल रहे हैं ताकि हमारे बाजार में उनकी आयातित वस्तुओं की बाढ़ ही आ जाए। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और विशाल आर्थिक आधार के कारण भारतीय उत्पादों की तुलना मं लाभप्रद स्थिति में हैं और वे बड़ी आसानी के साथ भारतीय उत्पादों को हमारे अपने बाजार से निकाल बाहर कर सकती हैं। हम इस तथ्य को दृष्टिलोप नहीं कर सकते कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बजट तो भारत सरकार के बजट से भी अधिक बड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में विदेशी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा की की बातें करना बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये हमारे अपने बाजार को खोलने का बहाना मात्र है। हमारे अर्थतंत्र पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इस पर भी भारत सरकार इन अपमानजनक शर्तों को स्वीकार कर रही है क्योंकि साम्राज्यवादी दबाव को झेलने की उसकी क्षमता का तेजी के साथ क्षरण हो रहा है।

43. क्योंकि विकसित पूंजीवादी देशों को बाजार की भारी आवश्यकता है इसीलिये वे भारत में अपने उत्पाद कोई भी हथकंडा अपना कर बेच रहे हैं। सरकार उनकी अनियमितताओं को रोकने के लिये अपना अधिकारों का प्रयोग करने और बेईमानी भारी प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने में अक्षम है।

44. वैश्वीकरण की बातें करने पर भी विकसित पूंजीवादी देश एक दूसरे के साथ प्रतियोगता करने के लिये क्षेत्रीय समूह

बना रहे हैं। युरोपीय आर्थिक भाईचारा, एशियान और नाफ्टा ही ऐसी क्षेत्रीय गुटबंदियां हैं जो विश्व बाजार को हथियाने के लिये एक दूसरी के साथ लड़ रही हैं। इन समूहों द्वारा अपने व्यापार युद्ध में भारत का प्रयोग एक बड़े रणक्षेत्र के रुप में किया जा रहा है। भारतीय कम्पनियों के आगे जीवित बने रहने के लिये विदेशी-सहयोगी को ढूंढने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है। हिन्दुस्तान लीवर एवं टोमको का प्रस्तावित विलीनीकरण, गोदरेज की कुछ इकाईयों का प्रोक्टर एण्ड गैम्बल में विलीन हो जाना, मल्होत्रा समूह का गिलेरी में प्रस्तावित विलय, पारले के हितों को कोका कोला ग्रुप द्वारा अपना लेना ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि भविष्य का घटना-विकास क्या होगा। अनेक भारतीय कम्पनियां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की कनिष्ठ सहयोगी बनने हेतु सौदेबाजी कर रही हैं।

45. भारत सरकार द्वारा अनेक रियायतें दिये जाने पर भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने भारी मुनाफे को सुनिश्चित बनाने के लिये और अधिक रियासतें देने के लिये दबाव डाल रही हैं। यद्यपि ऊर्जा उत्पादक इकाईयों में पूंजीनिवेश करने के लिये भारत सरकार ने 16% मुनाफे की गारंटी दी है तथापि वे अभी भी पूंजीनिवेश करने से कन्नी कतरा रहे हैं और अधिक रियासतें देने की मांग कर रहे हैं। इसके फलस्वरुप बिजली की दरों में भारी वृद्धि हो जाएगी। उन्हें विश्वास है कि वे जो कुछ भी चाहेंगी, उन्हें मिलेगा क्योंकि भारत के वित्त मंत्री उन्हें सब कुछ देने को तत्पर हैं। बस, उनके मांगने की देर है।

46. भारत के औद्योगिक उपक्रमों में बीमारी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। एसोचैम के अनुसार बीमार इकाईयों की रिकार्ड संख्या 4 लाख 7 हजार है। एक अनुमान के अनुसार इन इकाईयों के 30,000 करोड़ रुपये के बैंक खाते जाम कर दिये गए हैं। इनमें से अनेक बीमार इकाईयों को बनाए रखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार ट्रेड यूनियनों के साथ सहयोग करके कोई निश्चित कार्यनीति बनाए। जब तक सरकार ऐसी कुछ इकाईयों को बड़े व्यवसायी गृहों की बेईमाई भरी प्रतियोगिता से रक्षा नहीं करेगी तब तक ऐसी किसी भी कार्यनीति या समझौते को जीवंत करना सम्भव नहीं है। बाजार अर्थव्यवस्था को लागू करने से सदा लघु एवं परम्परागत उद्योगों के मूल्य पर इजारेदार घरानों की शक्ति बढ़ी है। अधिकांश बीमार उद्योगों को तालाबंदी की स्थिति में फंस जाना पड़ेगा जिससे लाखों श्रमिकों को अपने रोजगार से वंचित होना पड़ेगा। तालाबंदी की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिये ही मालिको द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 (ओ) को समाप्त करने की मांग की जा रही है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पहले ही सरकार पर निर्गम नीति को विधायी मान्यता देने के लिये दबाव डाल रही हैं। इसका अभिप्राय केवल यही है कि अपनी सद इच्छा से औद्योगिक इकाई को बंद करने के मालिक के नैसर्गिक अधिकार को स्वीकार कर लिया जाए।

47. उद्योगों की विनियमीकरण की प्रक्रिया से उद्योगपतियों की भारी संख्या को उन आर्थिक गतिविधियों में जहां अधिकतम मुनाफा है, शामिल होने का अवसर सुलभ हुआ है। क्योंकि बाजार सीमित है, इसलिये उद्योग की ऐसी क्षमता का सर्जन हुआ है जिसका उपयोग ही नहीं हो सकता। पिछले दो वर्षों में उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध

आंकड़ों के अनुसार नये पूंजीनिवेश की संरचना इस प्रकार है। पश्चिमी भारत 39%, उत्तर 26%, दक्षिण 19% और पूर्व 15% इत्यादि। यह पाया गया है कि विशेष क्षेत्रों में भी उद्योग मुख्यतया बंदरगाहों के इर्द-गिर्द ही विकसित हो रहे हैं क्योंकि वहां आयात-निर्यात की समस्याओं का निपटारा करना आसान होता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित विकास होगा और पिछड़े क्षेत्र नयी औद्योगिक इकाईयों को विकसित करने के लिये पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

48. इजारेदार गृहों के विकास पर सभी प्रतिबंधों की समाप्ति होने से उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लघु औद्योगिक संगठनों ने पहले ही नयी आर्थिक नीतियों के अपने क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में अपनी गम्भीर चिंताएं एवं आशंकाएं व्यक्त की हैं।

49. तथाकथित बम्बई क्लब द्वारा हाल ही में एक वक्तव्य जारी करके विदेशी पूंजीपतियों के उन प्रतिस्पर्धात्मक लाभों की ओर संकेत किया है, जो भारत सरकार की ओर से उन्हें सुलभ कराए गए हैं। क्लब ने मांग की है कि ऐसी रियायतें उन्हें भी दी जाएं।

पूंजी-विनिवेश घोटाला

50. विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पूंजी-विनिवेश कार्रवाईयों में निजी क्षेत्र की भागीदारी 'सीमित' रही है, अधिक लचीली व्यवस्था करके इसे और प्रोत्साहित करने और विदेशी पूंजीनिवेशकों को इसमें भाग लेने की अनुमति देने की आवश्यकता है। यह रेखांकित किया जाना चाहिये कि मूलभूत एवं सामरिक महत्व की लाभ पर चलने वाली 30 से अधिक सार्वजनिक इकाईयां के शेयरों का पूंजी-विनिवेश किये जाने के बाद भी ऐसे विचारों की अभिव्यक्ति की जा रही है। बैंकों से मांग की जा रही है कि वे सार्वजनिक इकाईयों में पूंजीनिवेश के सम्बन्ध में अधिक सामरिक दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें उन इकाईयों को बेच देना तक भी शामिल है। अत: आने वाले दिनों में लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों में पूंजी-विनिवेश के निहितार्थ को समझना कठिन नहीं है। पूंजी विनिवेश की प्रक्रिया में जिस प्रतिबद्धता का परिचय दिया जा रहा है उसकी 'हर्षद मेहता प्रकरण' से सहज ही तुलना की जा सकती है। शेयरों का मूल मूल्य कई बहाने बना कर बाजार मूल्य से कहीं कम निर्धारित किया गया है।

51. भारत सरकार के किसी औपचारिक निर्णय की घोषणा किये बिना सेल, हिन्दुस्तान जिंक, नैलको, आई पी सी एल, कोचीन रिफायनरीस एंड्रयू यूले,नेशनल फर्टिलाइज़र तथा फैक्ट के शेयरों की बिक्री की गई तथा विनिवेश के लिये कई अन्य उद्यमों की सूची तैयार ली गई है। सी ए जी ने रेखांकित किया है कि कुल बंडलों के 71% भाग की बिक्री एक बोली के आधार पर की गई है। जिन शेयरों का पूंजी विनिवेश हुआ है उन्हें तेजी के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ में

चले जाने की अनुमति दी गई है और इसके लिये कोई प्रक्रिया निश्चित नहीं की गई। प्रेस में एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार अलाहाबाद बैंक ने 10 फरवरी, 1992 को 13-12 करोड़ रुपये मूल्यका एक बंडल खरीदा। वह दो बार एक हाथ से दूसरे हाथ में गया और अन्तत: कुख्यात सिटी बैंक के पास पहुंच गया और वह 'न्यास' के रुप में 38.81 करोड़ रुपये के मूल्य पर। सी ए जी रिपोर्ट के अनुसार मूल मूल्यों में कमी करने के परिणामस्वरुप 3,442 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

52. निजी पूंजी को सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का उपहार देने के मामले में भी यही स्थिति हैं। इस्को का निजीकरण एक दुखंद प्रसंग है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस विशाल एवं प्राथमिक इस्पात कम्पनी की कुल परिसम्पत्ति जिसमें उसकी भूमि, उद्योग नगरी, उसकी खदाने इत्यादि भी शामिल हैं, का वर्तमान बाजार भाव लगभग 12,000 करोड़ रुपये है। बड़ी निर्जलज्जता के साथ इस तथ्य की उपेक्षा करके भारत सरकार ने इस्को की वर्तमान एक्टविटी का 392 करोड़ से 134 करोड़ रुपये का अवमूल्यन करने का निर्णय किया है और मैसर्ज मुकंर आयरन को ऐसे 75% शेयर जिनका अवमूल्यन किया जा चुका है, तट-फट खरीद लेने की पेशकश की गई है। इन 75% शेयरों के मूल्य को सेल द्वारा मैसर्ज मुकंद आयरन को दिया गया ऋण मान लिया जाएगा। यह ऋण ब्याज की रियासती दर पर दिया जाएगा और इसका भुगतान भी किश्तों में करना होगा।

53. मल्होत्रा समिति ने बड़ी निलज्जता से बीमा कम्पनियों का निजीकरण करने की सिफारिश की है। इसकी मांग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से ही गई थी। इससे विदेशी बीमा कम्पनियों को शोषण करने का एक और अवसर प्राप्त हो जाएगा।

54. नरसिम्हन समिति ने पहले ही बैंकिंग उद्योग का निजीकरण करने और विदेशी बैंकों की अधिक रियायतें देने की सिफारिश की थी ताकि वे (विदेशी बैंक) भारत में बैंकों की बड़ी जमा राशि को हड़प सकें। तथाकथित 'आर्थिक रुप से अलाभप्रद शाखाओं 'को बंद करने के लिये चिन्हित किया गया है। इसके परिणामस्वरुप एक लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों को रोजगार हानि झेलनी पड़ेगी।

बी आई एफ आर और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयां :

55. आज सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों के कर्मचारियों के विरोध में निहित स्वार्थों द्वारा शक्तिशाली प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्हें उनके उपक्रमों की बीमारी के लिये उत्तरदायी करार दिया जा रहा है। यहां बीमारी के कुछ महत्वपूर्ण कारकों की सूची तैयार करना न्यायोचित होगा। अनेक इकाईयां प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कारणों से बीमार हुई हैं। उनकी प्राथमिक अवस्था में गलत प्रौद्योगिकी उन पर थोपी गई थी। शायद बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव के

कारण ही। इसी तथ्य के चलते वहां अपनाई गई प्रौद्योगिकी को विकसित ही नहीं किया गया। ऐसी अनेक इकाईयों की बीमारी का कारण अविकसित एवं अप्रचलित प्रौद्योगिकी ही है। विभिन्न क्षेत्रों की अनेक इकाईयों के लिये आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी/आर्थिक योजनाएं बनाई तो गई किन्तु वर्षों तक उन्हें कार्यरुप ही नहीं दिया गया। इन इकाईयों को हुए घाटे के आंकड़े सही तस्वीर नहीं दिखाते अपितु लेखा सम्बन्धी धोखाधड़ी का प्रमाण ही देते हैं। वहां पर प्रशासकीय एवं भ्रष्टाचार की समस्याएं भी हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है।

५६. सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाईयों को लगभग समाप्त किये जाने की सम्भावना है जिनके मामले बी आई एफ आर को सौंपे गए थे, उनका निजीकरण भी किया जा सकता है। यह खतरा उस समय तक बना रहेगा जब तक ट्रेड यूनियन इस खेल को विफल नहीं बना देतीं। इन इकाईयों की प्रवर्तक के रुप में सरकार इनके पुनर्गठन के लिये एक पैसा भी खर्च करने से स्पष्ट इन्कार कर रही है। यहां तक कि बी आई एफ आर ने इन इकाईयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को भी स्वीकार नहीं किया है। इन मामलों की सुनवाई करते समय बी आई एफ आर खुले रुप से अधिकांश मामलों में सरकारी नीतियों की वकालत करती है और गम्भीरतापूर्वक उन पर विचार किये बिना उनके मामले को आगे बढ़ा देती है। यह भी नहीं सोचती कि थोड़ी सी पूंजी का निवेश करके क्या इन इकाईयों को आर्थिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य बनाया जा सकता है।

५७. प्रेस में विश्व बैंक को उद्धरित करते हुए कहा गया है, "सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों का निपटारा शीघ्र करो।" उसने "बी आई एफ आर" की शाखाओं को बढ़ाने और उसकी शक्तियों में वृद्धि करने का निर्देश भी दिया है ताकि बीमार इकाईयों को बंद कर सके। अत: यह स्पष्ट ही है कि सरकार ने ऐसी ही संस्तुतियां देने के लिये गोस्वामी समिति बनाई थी। और उसने ही उसे एस आई सी ए में संशोधन करने को कहा था समिति ने विश्व बैंक द्वारा निर्धारित तर्ज पर ही अपना राग अलापा था। उसने 'बीमार कम्पनियों का बिस्तर गोल करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिये 'फास्ट ट्रैक' न्यायाधिकरणों को स्थापित करने की सिफारिश की थी।' समिति की कुछ खतरनाक संस्तुतियां हैं 'आई डी एक्ट, एस आई सी ए'तथा बी आई एफ आर के कार्यों से सम्बन्धित कानूनों में भारी परिवर्तन किया जाए, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी कानूनों की समाप्ति, उनकी छंटनी का मार्ग प्रशस्त करने और बीमार इकाईयों की तालाबंदी जैसे लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। यहां तक कि पुनर्गठन योजनाओं की प्रक्रिया में भी कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की गई थी।

निर्गम नीति और एन आर एफ

५८. विश्व बैंक के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के 244 उपक्रमों में से ८२ को बंद कर दिया जाए। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का उद्धरण दिया गया था। इससे आगे जाते हुए उसने सार्वजनिक

क्षेत्र की 98 इकाईयों की पहचान बीमार इकाईयों के रुप में की थी जबकि उसने 'पाया' कि 58 इकाईयों तो गंभीर रुप से बीमार हैं। इन बीमार इकाईयों के साथ प्रत्यक्ष रुप से जुड़े कर्मचारियों की संख्या लगभग आठ लाख है। यहीं पर बस नहीं, यह अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिये कि छंटनी की तलवार केवल बीमार इकाईयों के कर्मचारियों के सिर पर ही नहीं लटक रही। लाभ पर चलने वाली इकाईयों में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र की प्रविष्टी और श्रमिकों को भर्ती करने और निकाल बाहर करने का अधिकार देने सम्बधी मालिकों की मांग माने जाने के फलस्वरुप इस वर्ग के कर्मचारियों पर भी छंटनी की गाज़ गिरने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। छंटनी की इस समस्या के पूरे आकार की समीक्षा करते समय अनियमित ठेका मजदूरों को भी ध्यान में रखना होगा।

59. समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा विरोध किये जाने पर भी राष्ट्रीय नवीकरण कोष के मामले में सरकार ने हठधर्मिता वाला रुख अपना रखा है। सर्वाधिक निंदा किये जाने योग्य बात तो यह है कि सरकार बीमार इकाईयों को बंद करने के लिये कोष उपलब्ध कराने को तो तैयार है किन्तु बीमार इकाईयों के पुनरुज्जीवन के लिये धन देने से इन्कार कर रही है और ऐसे मामले में भी सरकार का रुख नकारात्मक है जहां पुनरुज्जीवन के लिये थोड़ी धन राशि की आवश्यकत है। यहं तक कि सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बता दिया गया है कि उन्हें स्व: इच्छित सेवा निवृत्ति योजना में खर्च करने के लिये जो धन दिया गया है, इस पर भी दृष्टि रखी जाएंगी।

60. अब तक यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि विशेष त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति के साथ सरकार का व्यवहार बहुत ठंडा है, वह उसे गम्भीरता से नहीं लेती और इस प्रकार वह त्रिपक्षवाद का मजाक उड़ाती है। त्रिपक्षीय समिति की उसके गठन के पश्चात् केवल तीन बैठकें हुई है जबकि सरकार ने घोषण की थी कि उसकी बैठकें नियमित अंतराल में होती रहेंगी। इसके विपरीत त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की बैठकें नियमित नहीं होती। अधिक दुखदायी बात तो यह है कि सरकार समिति के निर्णयों को कार्यरुप नहीं देती और खुले रुप से अपने आश्वासनों को भंग करती है। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने ट्रेड यूनियन शिष्टमण्डलों को अनेक बार आश्वासन दिया किन्तु उन्होंने नियमित अंतराल में अभी तक समिति की बैठकें नहीं बुलाई।

61. जब बीमार इकाईयों के पुनरुज्जीवन हेतु धन जुटाने का प्रश्न सामने आता है तो सरकार 'संसाधनों की कमी' का रोना रोती है और इस प्रकार उनके घाटे को वर्षो तक बढ़ने दिया जाता है। 1991-92 के 16,262 करोड़ रुपये की तुलना में 1992-93 में राजस्व घाटा 16,733 करोड़ रुपये का था।

62. ट्रेड यूनियन आंदोलन को बहुत सीमा तक बेरोजगारी की समस्या का सामना करना होगा। तालाबंदी और औद्योगिक बीमारी के विरोध में कर्मचारियों के रोजगार को बचाने के संघर्ष का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सी आई टी यू को काम के अधिकार हेतु संघर्ष छेड़ने के लिये पहलकदमी करनी होगी और केवल इसी प्रकार श्रमिकों के हितों की

रक्षा की जा सकती है ।

63. कार्य समिति की भुवनेश्वर बैठक में निजी तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों की बीमार इकाईयों के श्रमिकों का सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया था । अभियान समिति तथा सी पी एस टी यू ने भी पहले ही ऐसे सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय किया था । तथापि अभी तक ऐसा कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता है । इससे बीमार तथा बंद औद्योगिक इकाईयों के श्रमिकों के आंदोलन पर दुष्प्रभाव पड़ा है ।

64. मूल्य वृद्धि का प्रश्न भी पिछले कुछ समय से गम्भीर होता चला गया है । नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने के पश्चात् पिछले अढ़ाई वर्षों में मूल्यों में 17 गुणा वृद्धि हुई है जिसका दुष्प्रभाव जनता के जीवन स्तर पर पड़ रहा है । हाल ही में अनाज, एल पी जी गैस, पेट्रोल एवं डीजल, चीनी के मूल्यों में बजट पूर्व वृद्धि से सर्व साधारण पर कमरतोड़ बोझ पड़ा है । जब हमारा सम्मेलन हो रहा होगा, तब रेलवे तथा आम बजट संसद में प्रस्तुत किया जा रहा होगा जिससे हमारे देश की जनता की कठिनाईयां और बढ़ जाएगी । मूल्य वृद्धि के विरोध में चल रहे संघर्ष को हमें अपनी गतिविधियों का महत्वपूर्ण पक्ष बनाना होगा ताकि सरकार नीतियों के प्रतिकार को तीव्रतर किया जा सके ।

65. भारत भर में जन-विरोध होने पर भी सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने से भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ेगा । जब दवाईयों के मूल्य बढ़ जाएंगे और कृषि निवेश में वृद्धि होगी तब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत की जनता को और अधिक लूटने की स्थिति में आ जाएगी ।

नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान

66. मजदूर वर्ग के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति को नरसिम्हा राव सरकार द्वारा नयी आर्थिक नीतियों की घोषणा करने के पश्चात् संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । इन नीतियों के विरोध में संयुक्त कार्रवाईयों का आयोजन करने के प्रश्न पर बी एम एस ठंडा रुख अपना रही है । इसके परिणामस्वरुप समिति जुलाई 1991 की अपनी बैठक में नयी आर्थिक नीतियों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना ही नहीं बना सकी । उसने केवल मजदूरों में अभियान चलाने का आह्वान किया था । इसलिये गैर-बी एम एस ट्रेड यूनियनों ने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में सीधे संघर्ष का कार्यक्रम बनाया । ऐसी ही परिस्थितियों में अभियान समिति अस्तित्व में आई । उसने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में सीधी कार्रवाईयों के कार्यक्रम बनाए और उन्हें कार्यरुप दिया ।

67.केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 13 अगस्त, 1991 को आयोजित पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में एक दिन की देश व्यापी हड़ताल

की आह्वान किया गया और नयी दिल्ली में 17 सितम्बर 1991 को विशाल सम्मेलन करने की योजना बनाई गई। उससे एक दिन पूर्व 16 सितम्बर 1991 को सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का एक सम्मेलन नयी दिल्ली में किया गया। दोनों सम्मेलनों ने भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में 29 नवंबर 1991 को राष्ट्र व्यापी हड़ताल का आह्वान किया। बी एम एस ने इस कार्रवाई में भाग नहीं लिया। देश भर में मजदूरों ने इसके लिये जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया और एक अनुमान के अनुसार 1,25,00,000, से अधिक मजदूरों ने हड़ताल की कार्रवाई में भाग लिया।

67. इस अवधि का एक उल्लेखनीय पहलू यह रहा कि अधिकारियों के संगठनों ने भी इन नीतियों का प्रतिकार करने में अभियान समिति के साथ सहयोग किया। यह अवश्य रेखांकित किया जाना चाहिये कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों, बीमा कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों, एयर लाइन्स कर्मचारियों से सम्बन्धित अनेक उद्योगवार फेडरेशनों ने भारी स्तर पर इस कार्रवाई में भाग लिया। अभियान समिति ने देश भर में सीधी कार्रवाई का अपना कार्यक्रम जारी रखा। इसकी एक कमजोरी यह रही कि रेलवे कर्मचारी आंदोलन जिसने सम्मेलनों एवं जन सभाओं में शिरकत की थी, हड़ताल की कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ। अभियान समिति ने अपने सघन अभियान के पश्चात् 16 जून 1992 को एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। यह हड़ताल पिछली हड़ताल की अपेक्षा बड़ी थी। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि मजदूरों में असंतोष बढ़ता ही चला जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार हड़ताल की इस कार्रवाई में 1.5 करोड़ से अधिक मजदूरों ने भाग लिया जबकि पिछली हड़ताल में 1.25 करोड़ मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया था। इस देशव्यापी कार्रवाईयों में बनाई गई एकता को उन संगठनों की ओर से भी असाधारण प्रत्युत्तर मिला जो औरपचारिक रुप से अभियान समिति में शामिल नहीं थे। देश भर में बढ़ रहे असंतोष को रेखांकित करते हुए अभियान समिति ने 25 नवंबर 1992 को संसद के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने का आह्वान किया। बोट क्लब में एक जनसभा की गई। उसकी उपस्थिति की संख्या अब तक की सर्वाधिक संख्या थी। एक अनुमान के अनुसार 10 लाख मजदूरों ने जनसभा में भाग लिया। उसी जनसभा में किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों इत्यादि के जन संगठनों को भी साथ मिला कर संयुक्त आंदोलन के घेरे को और विशाल करने का आह्वान किया गया। सम्मेलन ने यह आह्वान भी किया कि सभी जन संगठनों द्वारा एक दिवसीय भारत बंद का आयोजन किया जाए ताकि सभी जन संगठनों के शक्तिशाली स्वर की गूंज सारे देश में सुनी जा सके। जनसभा ने संघ-विहिप-भाजपा गठजोड़ द्वारा बाबरी मस्जिद का ध्वंस करने के लिये दी गई धमकी के दृष्टिगत बढ़ रही साम्प्रदायिकता के खतरे को भी रेखांकित किया और मजदूर वर्ग को साम्प्रदायिक एवं फूट डालने वाली शक्तियों के घृणित इरादों के विरोध में देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया।

69. यद्यपि बाबरी मस्जिद के विध्वंस और देश भर में साम्प्रदायिक दंगे होने के कारण आर्थिक नीतियों के विरोध में चल रहे संघर्ष को गहरा धक्का लगा है तथापि जनता के बिगड़ रहे जीवन स्तर ने सभी जन संगठनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिये अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। इसलिये 15 अप्रैल 1993 को नयी दिल्ली के तालकटोरा

स्टेडियम में एक विशाल सम्मेलन किया गया जिसमें विभिन्न जन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में संघर्षों को आगे बढ़ाने, केन्द्रीय सरकार की आर्थिक नीतियों तथा साम्प्रदायिकता के विरोध में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच की स्थापना करने का निर्णय किया गया। इस सम्मेलन ने कार्रवाई का चरणबद्ध कार्यक्रम जिसमें 19 अगस्त 1993 को सामूहिक गिरफ्तारियां देने और 9 सितम्बर 1993 को भारतबंद एवं एक दिवसीय औद्योगिक हड़ताल की कार्रवाईयां भी शामिल हैं, बनाया गया। सम्मेलनों में बनाए गए कार्यक्रमों की श्रृंखला की तैयारी स्वरुप उठाए गए कदम के रुप में 10 लाख से अधिक लोगों ने देश भर में सामूहिक गिरफ्तारी के कार्यक्रम में भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संगठित किया गया यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था।

70. इस कार्यक्रम ने भारत बंद के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संगठित करने के लिये अत्यंत अनुकूल स्थितियां उत्पन्न की थीं। 9 सितम्बर का भारत बंद अभूतपूर्व था। पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु और कर्नाटक में अच्छी तैयारी के फलस्वरुप बंद लगभग सम्पूर्ण जबकि देश के दूसरे भागों में आंशिक रहा। गुजरात जैसे राज्यों में भी जहां संयुक्त आंदोलन बहुत कमजोर है औद्योगिक हड़ताल तथा बंद की कार्रवाई का अच्छे प्रभाव की अनुभूति की गई। डाक एवं तार, दूर संचार, आयकर एवं लेखा विभागों में हड़ताल बहुत ही अच्छी रही। 50 लाख से अधिक राज्य सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया। तथापि रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की कार्रवाई में भाग नहीं लिया। बैंकिंग उद्योग, बीमा क्षेत्र, रक्षा उद्योग, एयर लाइन्स, उर्वरक कारखानों, कोयला खदानों इत्यादि के कर्मचारियों ने अच्छी हड़ताल की जबकि गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने पिछली कार्रवाईयों की अपेक्षा इस हड़ताल में भारी संख्या में भाग लिया।

71. इस्पात उद्योग में 4 अगस्त 1993 की कलकत्त के सफल सम्मेलन के पश्चात् इंटक और बी एम एस ने इस्को के निजीकरण तथा सार्वजनिक उद्यमों में पूंजी विनिवेश की नीति के विरोध में 7 सितम्बर की हड़ताल में भाग लिया। बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिये के अनेक भागों में किसानों, छात्रों, युवाओं और महिलाओं को लामबंद किया गया। इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सरकारी प्रचार और इस बात को देखते हुए कि कांग्रेस और भाजपा ने इस जन-कार्रवाई का विरोध किया था, 9 सितम्बर का बंद सफल रहा क्योंकि लाखों लोगों ने इस कार्रवाई में भाग लिया था। इससे देश के सर्व साधारण के बीच बढ़ रहे असंतोष का ही संकेत मिलता है। जब गाट के प्रमुख पीटर सदरलैंड 28 अक्तूबर 1993 को दिल्ली आए तो राष्ट्रीय मंच ने बौद्धिक सम्पदा पर राष्ट्रीय कामकाजी गुट के सहयोग से विरोध प्रदर्शन संगठित करने का निश्चय किया। संसद के समक्ष भारी प्रदर्शन किया गया। एक 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ भेंट करके पीटर सदरलैंड की यात्रा का विरोध किया। डंकल प्रस्तावों के विरोध में 3-9 दिसम्बर 1993 तक देश भर में मनाए गए सप्ताह को भरपूर प्रत्युत्तर मिला। केवल दिल्ली में ही 32 संसद सदस्यों सहित 5000 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी। इन कार्यक्रमों की समीक्षा करने के पश्चात् जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच ने देश भर में सम्मेलन करने जत्था मार्च करने और जन सभाएं आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है।

इसकी परिणिति 5 अप्रैल 1994 को संसद के समक्ष भारी जन प्रदर्शन करने के रुप में होगी। सी आई टी यू यूनियनों को अपनी गतिविधियां तेज कर देनी चाहिये ताकि देश के सभी भागों में इस कार्यक्रम को भी सफलता पूर्वक सम्पन्न किया जा सके।

72. क्योंकि जनता का जीवन स्तर तेजी से बिगड़ता चला जा रहा है, इसलिये वह (जनता) और भी जुझारू संघर्ष करना चाहती है। हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों को कार्यरुप देने की प्रक्रिया को बदलने के लिये इन नीतियों के शारीरिक विरोध की नयी विधियां तलाश करनी होंगी। हमने अब तक जो संघर्ष किये हैं उनसे तथाकथित सुधारों की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायता मिली है। तथापि हमें और शक्तिशाली संघर्ष छेड़ना होगा ताकि इस प्रक्रिया को पूर्णतया बदला जा सके। हमें लोगों में आई जागरुकता के दृष्टिगत संघर्ष के उपयुक्त उच्च रुपों का पता लगाना होगा। मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि सी आई टी यू यूनियनें इस कसौटी पर खरा उतरेंगी और नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों के द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करेंगी।

साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के हथकण्डे :

साथियों,

73. जहां मजदूर वर्ग भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भीषण संघर्ष में उलझा हुआ है वहीं साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियां देश की एकता तथा अखंडता के आधार पर ही चोट कर रही हैं। ये शक्तियां असल मुद्दों की ओर से जिनका सामना पूरा देश कर रहा है, जनता का ध्यान हटा रही हैं और भारत की जनता के विभिन्न वर्गों एवं समुदायों के बीच फूट के बीच बोने का प्रयास कर रही हैं।

74. संघ-विहिप-भाजप गठजोड़ के नेतृत्व में साम्प्रदायिक शक्तियां देश भर में अल्प संख्यकों विशेष रुप से मुसलमानों के विरोध में विषाक्त घृणित प्रचार कर रही हैं। वे चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिन्दू शावनवाद को उभार रही हैं। उनका अंतिम लक्ष्य केन्द्र में सत्ता प्राप्त करना है। हमारे लिये चिंता का विषय है कि मजदूर वर्ग का एक भाग उनके प्रचार के बहाव में बह गया है जिसका हमारे वर्ग की एकता पर दुष्प्रभाव पड़ा है। मुसलमान, सिख और ईसाई मूलवादी भी जनता के मध्य धार्मिक शावनवाद को उभारने के लिये सक्रिय हैं। सभी मूलवादी शक्तियां अपने घृणित इरादों को पूरा करने के लिये देश में व्याप्त असंतोष से लाभ उठाना चाहती हैं।

नरसिम्हा राव इन शक्तियों के विरुद्ध लड़ने के स्थान पर इनके साथ समझौता करने और इनके आगे आत्मसमर्पण करने का प्रयास कर रही है। इन घटनाओं जिनकी परिणित 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रुप में हुई, ने स्पष्ट रुप से प्रमाणित कर दिया है कि यदि भारत सरकारी बाबरी मस्जिद की रक्षा करने में गम्भीर होती तो वह हिन्दू शासनवादियों जिन्होंने खुले रुप में बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने की धोषणा की थी, के विरुद्ध कठोर काईवाई अवश्य करती। केन्द्रीय सरकार के पास घटनास्थल पर विशाल भीड़ को एकत्रित करने से रोकने के लिये पर्याप्त शक्तियां थीं और वह बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मन्दिर का निर्माण करने के लिये प्रतिबद्ध भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर सकती थी।

भारत सरकार की नर्मी को साफ तौर पर इसी तथ्य से ही देखा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने और उसके स्थान पर मन्दिर के अस्थायी ढांचे का निर्माण पूरा होने के पश्चात् ही सेना ने वहां हस्तक्षेप किया। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया जा रहा था तब सेना केवल तीन किलो मीटर की दूरी पर मूक दर्शक बनी बैठी रही। सेना तभी घटनास्थल पर पहुंची जब कार सेवक विजयोल्लस में वहां से प्रस्थान कर चुके थे।

75. साम्प्रदायिक विभीषिका जिसने देश के अनेक भागों को अपनी चपेट में ले लिया था, में एक बार फिर साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध दृढ़ कार्रवाई करने में कांग्रेस सरकारों की विफलता को इंगित कर दिया। केन्द्रीय सरकार द्वारा आधे मन से उठाए गए कदमों ने अग्नि को और प्रज्वलित करने का काम ही किया। ऐसी रिपोर्टं मिली हैं कि कांग्रेस इ शासित अनेक राज्यों में पुलिस ने भी अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार में भाग लिया था। प्रतिबंध लगाए जाने से भी संघ भी गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वह खुले रुप से काम कर रहा है, और मुसलमानों के विरुद्ध साम्प्रदायिक घृणा का प्रचार कर रहा है। संसद में जिस ढंग से धार्मिक विधेयक लाया गया और अंततः उसे वापस ले लिया गया उससे केवल इन शक्तियों को ही मजबूती मिली है। भारत सरकार ने भाजपा की तुलना अन्य धर्मनिर्पेक्ष विपक्षी दलों के साथ की है। जब सरकार ने बोट क्लब पर भाजपा ने जनसभा करने पर प्रतिबंध लगाया तो उसने महाराष्ट्र में धर्मनिर्पेक्ष विपक्षी दलों द्वारा साम्प्रदायिकता के विरोध में आयोजित की जाने वाली जनसभा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। उसने शिव सेन के गुण्डों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जो खुले रुप में मुसलमानों और गैर-महाराष्ट्री लोगों पर धावे बोल रहे थे।

76. मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपने अनुभवों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों के चरित्र को देख लिया है। इस पार्टी ने इन राज्यों की जनता और मजदूर वर्ग के साथ जो वादे किये थे, उन सभी को सत्ता में आने के पश्चात् रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। स्वाभाविक ही है, यह पार्टी लोगों से कटती चली गई। हिन्दुत्व के मंच का दुरुपयोग करके भी यह पार्टी कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकी है और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। तथापि हमें अभी शांत होकर बैठना नहीं

चाहिये क्योंकि जनता के एक वर्ग के दिल में सम्प्रदायिक विचारधारा गहराई तक घर कर चुकी हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने घृणित इरादों की पूर्ति के लिये कुछ भी करने को तत्पर है। ऐसी स्थिति में उनकी विचारधारा के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाना होगा ताकि उन्हें देश की जनतांत्रिक जनता द्वारा बुरी तरह ठुकरा दिया (पराजित) जाए।

77. पाकिस्तान की ओर से पृथकतावादी गतिविधियों को नैतिक एवं भौतिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के परिणामस्वरुप कश्मीर निरंतर गर्म क्यारी बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा हाल ही में दिये गए वक्तव्यों से कश्मीर में साम्राज्यवादी इरादे उभर कर सामने आ गए हैं। भारत सरकार ने जिस ढंग से हजरत बल मस्जिद के प्रकरण को निपटाया है, उससे कश्मीर समस्या को हल करने में किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। कुछ सीमा तक स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है किन्तु संकटपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार ने कश्मीर को उचित स्वायत्ता सुनिश्चित करके समस्या का राजनीतिक समाधान ढूँढ निकालने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि भारत सरकार प्रशासकीय कदमों और सैनिक कार्रवाई पर ही निर्भर करती रही तो समस्या का समाधान कभी भी निकाला नहीं जा सकेगा।

78. पंजाब की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है किन्तु कांग्रेस सरकार अभी भी अपने पार्टी हितों को सामने रख कर इस प्रश्न को देख रही है और उसने राजीव लौंगोवाल समझौते के आधार पर पंजाब समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने का प्रयास ही नहीं किया है। यद्यपि उग्रवादी जनता से दूर होते चले जा रहे हैं तथापि उनकी गतिविधियां पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं और वे निरंतर साम्राज्यवादी एजेंसियों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

79. असम में स्थिति अभी भी गम्भीर बनी हुई है। तथाकथित असम आंदोलन के पीछे सक्रिय शक्तियों का विखण्डन होने पर भी आतंकवादी तथा पृथकतावादी तत्व सक्रिय हैं। बोडोलैंड आंदोलन ने हिंसक रुप धारण कर लिया है। इसकी परिणिति बोडो सुरक्षा बलों द्वारा किये गए बोगाईगांव नरसंहार के रुप में हुई जबकि 30 व्यक्ति मारे गए, 35 बेघर हो गए और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। स्वायत्तशासी राज्य के लिये समझौता होने पर भी सैकिया सरकार तुरंत कदम नहीं उठा रही और वह अपने दलीय हितों के अनुकूल उसे टालते रहने की राजनीति कर रही है।

80. असम राज्य में उल्फा उग्रवादियों की समस्या अभी तक बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ संघर्ष करने का दिखावा कर रही है किन्तु इसके साथ-साथ अपने दलीय हितों के लिये उनके साथ गुप्त समझौता भी किये हुए है। उल्फा उग्रवादियों को भारी मात्रा में शस्त्रास्त प्राप्त हो रहे हैं और उसके उत्तरी-पूर्वी भारत में अन्य आतंकवादी गुटों के साथ सम्बन्ध भी है। विदेशी शक्तियों द्वारा भारत में अस्थिरता लाने हेतु खेले जा रहे खेल के कारण वर्तमान विस्फोटक स्थिति और भी उलझ गई है।

81. ट्रेड यूनियन आंदोलन को अधिक दृढ़ता के साथ साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखना होगा। वर्तमान परिस्थतियों में ऐसे संघर्षों को चलाने की भारी आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी उन्मत्ता से कांग्रेस-इ के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरने का प्रयास कर रही है और वह जनता की कांग्रेस-इ विरोधी भावनाओं से लाभ उठाने के चक्कर में है। हमें ऐसी स्थिति को जारी रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये वाम पक्षी जनतांत्रिक, देशभक्त और धर्मनिर्पेक्ष शक्तियों को विशाल स्तर पर लामबंद करना होगा ताकि जनता के सामने कांग्रेस-इ का सही विकल्प प्रस्तुत किया जा सके और वह भाजपा या अन्य विभाजक के प्रचार में वह न जाएं।

82. यद्यपि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन पूरी दृढ़ता को साथ साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के विरुद्ध खड़ा रहा है तथापि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिये काफी कुछ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता अभियान द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान में विशाल स्तर पर जनता से सम्पर्क स्थापित करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। यद्यपि इस अवसर का पूरा लाभ उठाया नहीं जा सका तथापि हमने अपनी सदस्य संख्या से कुछ कम संख्या में लोगों के हस्ताक्षर कराए हैं। जब इंटक ने इस अभियान का समर्थन किया तब भी विशाल स्तर पर जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करने का अच्छा अवसर था किन्तु हम उससे भी पूरी तरह लाभ नहीं उठा सके। यह भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है कि साम्प्रदायिक दंगों के समय हमने जितनी भूमिका निभाई, उसकी जनता के अनेक वर्गो द्वारा सराहना की गई है तथापि साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा खड़ी की गई समस्या के परिमाण की अपेक्षा हमारी भूमिका प्रतीकात्मक ही है। मजदूर वर्ग तथा लोकतांत्रिक आंदोलन ही अल्पसंख्यकों में विश्वास की भावना उत्पन्न कर सकता है क्योंकि देश में वही सच्ची धर्मनिर्पेक्ष शक्ति हैं। अत: सी आई टी यू को देखना होगा कि हमारी यूनियनें साम्प्रदायिकता विरोधी संघर्ष में अधिक से अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं तथा हम भारत की धरती से साम्प्रदायिकता के विषाणुओं का सफाया कर सकें।

83. पंजाब में हमारे साथियों ने सिख मूलवादियों और खालिस्तानी तत्वों के विरोध में अपना संघर्ष लगातार जारी रखा है। इसका मजदूरों के बीच अच्छा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि हमें इन संघर्ष में अपने अनेक बहुमूल्य साथियों से हाथ धोना पड़ा है तथापि उनका रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा। असम तथा त्रिपुरा में इस पूरी अवधि में हमारे साथियों ने विभाजक शक्तियों के विरोध में अथक संघर्ष किया है। फिर भी हमें अपने प्रयासों में और तेजी लानी होगी ताकि वे देश की एकता तथा अखण्डता के साथ द्रोह न कर सकें।

सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों का आंदोलन

84. सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड यूनियनों की समिति (सी पी एस टी यू) सार्वजनिक इकाईयों में औद्योगिक बीमारी, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम किये जाने एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आर्थिक मुद्दों को लेकर समय-समय पर

विभिन्न आंदोलन एवं काईवाईयों संबंधी कार्यक्रम चलाती रही है। समिति की विस्तृत बैठक 12 सितम्बर 1992 को नयी दिल्ली में हुई। इस बैठक में आंदोलन का चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा देश भर में आधे घंटे तक हड़ताल करने का कार्यक्रम भी शामिल था। समिति की एक और विस्तृत बैठक 3 तथा 4 दिसम्बर 1992 को हैदराबाद में हुई। इसमें दीर्घावधि की कार्रवाई योजना बनाई गई। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा देश भर में 20-22 अप्रैल 1993 को 72 घंटों की हड़ताल करने का कार्यक्रम भी शामिल था। तथापि बी एम एस ने बाद में अपना बादा तोड़ दिया और वह समिति से बाहर निकल गई। यही नहीं, इंटक ने भी उन्हीं मुद्दों पर 19 मार्च 1993 को हड़ताल करने की घोषणा कर दी। समिति ने इंटक से अनुरोध किया कि हड़ताल के लिये एक संयुक्त तिथि निश्चित की जाए, किन्तु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। हड़ताल की कोई तैयारी नहीं थी और अंततः सरकार द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि त्रिपक्षीय महंगाई भत्ता समिति की संस्तुतियों के अनुरूप महंगाई भत्ते की दर 1.65 रुपये से बढ़ा कर 2 रुपये कर दी जाएगी, 16 मार्च 1993 को हड़ताल वापस ले ली गई। इस प्रकार इंटक ने समिति के साथ द्रोह किया। समिति के कुछ घटकों द्वारा हड़ताल के लिये नोटिस नहीं दिये गए। अंततः केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा कुछ और मांगों को स्वीकार कर लिये जाने की स्थिति में हड़ताल वापस ले ली गई।

85. समिति (सी पी एस टी यू) ने 'सार्वजनिक क्षेत्र पर नयी आर्थिक नीतियों के प्रभाव' विषय पर 15 तथा 16 जुलाई 1993 को नयी दिल्ली में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसे सेल, कोल इंडिया, एन टी पी सी, सी ई एल, एन डी एम सी जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के सी एम डी/निदेशकों ने सम्बोधित किया। अन्य विशिष्ट वक्ता थे : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व अधिकारी डाक्टर डेवीसन बोधो और भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री डाक्टर अरुण घोष। इंटक के महासचिव गोपेश्वर ने भी संगोष्ठी में भाषण दिया था। तेल उद्योग में आत्म निर्भरता के विषय पर 1 तथा 2 सितम्बर 1993 को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में रेखांकित किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं से निपटने में हमारी पहलकदमी कहां तक कारगर सिद्ध होगी।

86. समिति की अंतिम विस्तृत बैठक 6 नवंबर 1993 को कलकत्ता में हुई। उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आह्वान किया गया कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के विखंडन के विरोध में बड़ी जन-कार्रवाईयां करने के लिये तैयार रहें। इसमें कार्रवाई के चरणबद्ध कार्यक्रम करने का निर्णय किया गया। इसमें उल्लेखनीय कार्यक्रम औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के विरोध में 7 दिसम्बर को राष्ट्रीय विरोध दिवस तथा 3 से 9 दिसम्बर 1993 तक राष्ट्रीय विरोध सप्ताह मनाना था। इसकी परिणिति राष्ट्रीय सम्प्रभुता की रक्षार्थ तथा डंकल प्रस्तावों के विरोध में 9 दिसम्बर 1993 को आयोजित एक जनसभा के रुप में हुई। इस संदर्भ में समिति के संगठन और कामकाज को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि यह प्रभावशाली ढंग से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये संघर्ष कर सके।

87. समिति (सी पी एस टी यू) की बैठक से पूर्व समन्वय समिति की बैठक करना हमारी नियमित कार्रवाई बन चुकी है

ताकि हम समिति की बैठक से पूर्व उसके सामने प्रस्तुत होने वाले मुद्दों पर अंतिम रूप से अपने रुख का निर्धारण कर सकें। तेजी के साथ हमारे सामने उपस्थित होने वाले मुद्दों पर तुरंत विचार करने के लिये समन्वय समिति के सुनियोजित एवं अधिक नियमित बैठकें होनी चाहियें। केन्द्र में साथियों की कमी होने के कारण समिति के अनेक महत्वपूर्ण कार्य दोषपूर्ण रह जाते हैं। मेरे उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है कि कामरेड जीवन राय सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों की समन्वय समिति के संयोजक के रुप में काम करेंगे।

88. सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग सभी प्रमुख इकाईयों में अंतिम वेतन सम्बन्धी समझौते की अवधि 1991 के अंत में समाप्त हो गई थी। किन्तु सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी विभाग ने प्रधानमंत्री की स्वीकृति से वेतन-वार्ताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथापि सरकार को आंदोलन जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस भी शामिल है, के आगे झुकना पड़ा और अंतत: प्रतिबंध हटा दिया गया। डी पी ई के अव्यवहारिक, अपरिभाषित एवं मनमाने निदेशों के कारण वेतन समझौता वार्ताएं सार्थक नहीं हो सकीं। ट्रेड यूनियनों ने इन निदेशों के प्रति अपना भारी रोष व्यक्त किया था।

89. सरकार के विचाराधीन नये निदेशों की अवधारणा वेतन वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत को 19% तक निर्धारित करना और समझौते की अवधि पांच वर्ष करना है। प्रबंधन के लिये पूर्व शर्त मुनाफा नहीं होगा अपितु घोषित किये जाने वाले कुछ लाभांश होंगे। दूसरी शर्तें हैं : वेतन वृद्धि के कारण निर्धारित मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी, इत्यादि।

90. वेतन समझौते में अभूतपूर्व देरी होने के कारण कर्मचारियों के मध्य गम्भीर रोष पाया जा रहा है। तथापि कुछ उद्योगों ने पहले ही अग्रिम एकमुश्त तदर्थ वृद्धि के रुप में अंतरिम राहत दी है। नये निदेशों के अन्तर्गत वेतन समझौता वार्ताओं की प्रगति पर निर्भर रहते हुए भी ट्रेड यूनियन आंदोलन को आने वाले दिनों में उन मुद्दों पर अपने रुख का निर्धारण करना होगा।

91. इस सम्बन्ध में यह रेखांकित करना आवश्यक हो जाता है कि बीमार इकाईयों के कर्मचारी स्पष्ट रुप से इस मुद्दे पर अधिक आंदोलित नहीं हैं क्योंकि उन्हें इस समय अपने अस्तित्व की रक्षा करने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें अच्छी चलने वाली इकाईयों में उच्च वेतनों के लिये संघर्ष और इन उद्योगों की बीमारी को दूर करने के संघर्ष अर्थात दोनों का एकीकरण करना होगा। केवल ऐसा करके ही आंदोलन में एकता लाने के काम में सहायता मिल सकती है।

92. सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते के प्रश्न का 1.1.1992 से 2.00 रुपये प्रति बिन्दु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता लागू किये जाने के कारण आंशिक रूप से समाधान हो गया है। सरकार ने परिवर्तनीय

महंगाई भत्ते की किश्त प्रणाली को सिद्धांत रुप में स्वीकार कर लिया है। बी एम एस द्वारा अलग रुख अपनाए जाने के कारण यह मामला लम्बित हो गया है। अंतत. उसे अंतिम रूप दे दिया गया और संयुक्त सहमति वाला सुझाव 22 नवंबर 1993 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब हमें सार्वजनिक क्षेत्र में महंगाई भत्ते के प्रश्न पर त्रिपक्षीय बैठक शीघ्र बुलाने के लिये सरकार पर दबाव डालना होगा।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये संघर्ष

साथियो,

93. हम उद्योगों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जो भारत की कुछ श्रमशक्ति का लगभग 85% हैं, के मध्य अपनी गतिविधियों का प्रसार करने के लिये प्रयासरत हैं। हम बीड़ी निर्माण, हरकरघा, पावर लूम, भट्टा, पत्थर खदान, टैनरीज़, केमिकल्स, गारमेंट उद्योग जैसे उद्योगों के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संगठित कर सके हैं। 1990 में हुई कानपुर जनरल कौंसिल की बैठक में बनाए गए 22 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विभिन्न राज्यों तथा अखिल भारतीय स्तर पर संघर्ष किये गए हैं। असंगठित श्रमिकों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की पहली बैठक पानीहारी, पश्चिम बंगाल में हुई। असंगठित श्रमिकों की समन्वय समिति का गठन सी आई टी यू के सातवें सम्मेलन में किया गया था। 1-3 नवंबर 1992 को आयोजित सम्मेलन में इस उपेक्षित क्षेत्र के श्रमिकों की मांगों को मनवाने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल कर आह्वान किया गया। सी आई टी यू द्वारा 14 जुलाई 1993 को पहली स्वतंत्र रुप से सफलतापूर्वक ऐसी हड़ताल संगठित की गई थी। यह अपनी ही तरह की पहली हड़ताल थी। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और दिल्ली में यह पूर्ण रही। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार व राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यह प्रभावशाली रही जबकि मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हड़ताल एवं प्रदर्शन किये गए। कुछ स्थानों पर अन्य ट्रेड यूनियनों ने भी हड़तमल में भाग लिया। जन हस्ताक्षर अभियान के अन्तर्गत लगभग 2 लाख लोगों से असंगठित श्रमिकों की मांगों के लिये हस्ताक्षर कराए गए जिन्हें लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया। इन मांगों में न्यूनतम वेतन, श्रम कानूनों को लागू करने, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कदम उठाने जैसी मांगें शमिल थीं। विभिन्न राज्यों से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने 9 सितम्बर 1993 के भारत बंद में पूर्व की दो हड़तालों की उपेक्षा अधिक संख्या में भाग लिया। हमने बीड़ी मजदूरों की अलग से अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई हैं। उसका अखिल भारतीय सम्मेलन 3-5 दिसम्बर, 1993 तक कन्नानूर में हुआ था।

94. यद्यपि हमने पूरी गम्भीरता के साथ इस काम का बीड़ा उठाया है तथापि हम अधिक से अधिक यही कह सकते हैं कि हमने शुभारम्भ कर दिया है। यह क्षेत्र अपने आकार की दृष्टि से इतना बड़ा है कि हमें इन नये क्षेत्रों में काम करने के लिये भारी संख्या में काडर की आवश्यकता पड़ेगी ताकि इस क्षेत्र में तीव्र गति से ट्रेड यूनियन आंदोलन को विकसित

किया जा सके। इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है। उन्हें यूनियन की गतिविधियों में शामिल करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। इस क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिये काडर के विकास कार्य को उनकी विशेष समस्याओं के दृष्टिगत उचित महत्व देना होगा। इसलिये सी आई टी यू केन्द्र ने दो कक्षाओं का आयोजन करने का निर्णय किया है। एक कक्षा असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा दूसरी इसी क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं के लिये। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिये कक्षा के आयोजन में सहयोग देने पर सहमत हो गया है।

न्यायोचित पेंशन योजना के लिये संघर्ष

95. भारत सरकार द्वारा तैयार की गई पेंशन योजना केवल भविष्य निधि योगदान को पेंशन योजना में तबदील करने के आधार पर पेंशन प्रदान करती है। परिवार पेंशन योजना से श्रमिकों की लाखों विधवाओं को पेंशन न देकर बचा कर रखे गये श्रमिकों के 5000 करोड़ रुपये से अधिक के संचित कोष को नये पेंशन कोष में मिलाया जाएगा। यहीं नहीं पेंशन-योग्य वेतन में पिछले वेतन की अपेक्षा पहले 60 महीनों के समानुपातिक वेतन को आधार माने जाने के कारण भारी कमी हो जाएगी। पेंशन को मूल्य सूचक अंक से जोड़ा नहीं गया जैसा कि केन्द्रीय सरकार की योजना के मामले में किया गया था। सी आई टी यू ने भविष्य निधि तथा गैच्यूटी के साथ-साथ तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन देने की मांग की थी। सी आई टी यू ने सबसे पहले इस योजना का विरोध किया था जबकि दूसरी ट्रेड यूनियने बाद में इसके विरोध में सामने आई।

96. कोयला तथा इस्पात उद्योगों में इस योजना में समान योगदान के लिये संयुक्त समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। इसके अन्तर्गत श्रमिकों के वेतन से 2% राशि 1989 से काटी जाती रही है किन्तु प्रबंधन ने अपना वादा पूरा नहीं किया है।

97. श्रम मंत्रालय में 4 मई, 1993 को हुई बैठक में सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने पेंशन योजना की आलोचना करते हुए इसे बदलने की मांग की थी। केन्द्रीय श्रम मंत्री योजना में सुधार लाने को सहमत हो गए थे किन्तु वह योजना में प्रबंधकों का योगदान सुनिश्चित करने पर सहमत नहीं हुए। केन्द्रीय सरकार संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बना रही थी जिससे सरकार पेंशन योजना बनाने और फिर उसे अंतिम रुप देने की स्थिति में आ जाए। सी आई टी यू ने सुझाव दिया था कि पहले योजना को अंतिम रूप दिया जाए और उसके बाद संसद में विधेयक लाया जाए। सरकार को यह सुझाव स्वीकार्य नहीं था।

98. इसी मध्य वित्तीय क्षेत्र में कर्मचारियों ने निरंतर आंदोलन करके पेंशन पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसका

श्रेय संयुक्त संघर्ष समिति को ही जाता है। उसने अनेक हड़तालें संगठित करके सरकार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन (ए आई बी ई ए) के साथ पहले हुई सहमति के ऊपर तथा उस से भी अधिक रियासतें देने को बाध्य किया है।

99. इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि सी आई टी यू पेंशन के प्रश्न पर अपना अभियान जारी रखे और इस पर जहां तक हो सके श्रमिकों की विशाल से विशालतर एकता स्थापित करने का प्रयास करे। इस सम्बन्ध में हमें प्रशंसात्मक दृष्टि से फिलिप्स इम्पलाईज यूनियन, बम्बई द्वारा किये गए काम को रेखांकित करना चाहिये जिसने भारत भर में योजनाबद्ध ढंग से अभियान चला कर सरकारी योजना के अंधकारमय पक्ष को उजागर किया है।

100. ऐसी स्थिति में जब वर्तमान लाभों पर तीव्र हमले हो रहे हों, पेंशन के लिये संघर्ष कठिन होने पर भी श्रमिकों में लोकप्रिय होता चला जा रहा है। हमें इस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिये ताकि न्यायोचित पेंशन योजना की मांग के पक्ष में अधिक से अधिक श्रमिकों की लामबंदी सुनिश्चित की जा सके।

बोनस अधिनियम का मजाक

101. भारत सरकार ने बोनस अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान की वेतन सीमाओं को समाप्त् करने से इन्कार करके विलम्बित वेतन के रूप में बोनस की पूरी धारणा की ही मजाक उड़ाया है। सम्पूर्ण ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा संयुक्त रूप से मांग किये जाने पर भी सरकार निरंतर वेतन सीमा-समाप्ति का विरोध कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में श्रमिकों की भारी संख्या जो 2500 रुपये से अधिक वेतन पाती है, बोनस अधिनियम के घेरे से बाहर चली गई है और श्रमिकों की बड़ी संख्या को तो पात्रता पर 1600 रुपये की सीमा होने के कारण न्यूनतम 8 1/3% बोनस भी नहीं मिलता।

102. केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने मंत्री मण्डल को सुझाव दिया था कि 3500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस लेने के पात्र माना जाए और अधिक से अधिक बोनस 2500 बोनस रुपये किया जाए। सरकार ने इस सुझाव को भी स्वीकार नहीं किया है। इसके कारण श्रमिक वर्ग में रोषपूर्ण प्रतिक्रिया हुई है। श्रम मंत्री के सुझाव से श्रमिकों को कुछ राहत तो मिल सकती है किन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि श्रमिकों की भारी संख्या 3500 रुपये की वेतन सीमा से ऊपर चली गई है। इस समस्या का समाधान वेतन सीमा पूर्णतया समाप्त करने से ही निकल सकता है।

103. वर्तमान उपलब्ध अतिरिक्त फार्मूले को समाप्त करने की भी आवश्यकता है जो बुरी तरह मालिकों के पक्ष में झुका हुआ है। सेट-आन तथा सेट आफ की वर्तमान व्यवस्था और इसके साथ पिछले परिव्यय की धारणा से केवल श्रमिकों

के बोनस की राशि की मात्रा ही कम होती है। तथ्य तो यह है कि अनेक निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ऐसे समझौते हुए हैं जिनके अन्तर्गत अधिनियम में उपलब्ध फार्मूले से अधिक बोनस प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इससे वर्तमान फार्मूले का प्रपंच ही उजागर होता है। इसीलिये ट्रेड यूनियनों को सकल लाभ के हिसाब के आधार पर बोनस का भुगतान करने की मांग करनी चाहिये। यही नहीं आय-व्यय के हिसाब में मालिकों को अपना पक्ष मजबूत करने का अवसर मिल जाता है और श्रमिक बोनस से वंचित हो जाते हैं। इस कानून के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनें आय-व्यय के हिसाब को चुनौती नहीं दे सकेंगी जबकि पिछले कानून को अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त था और मालिकों को प्रमाणित करना पड़ता था कि उनका हिसाब ठीक है।

104. एक दशक से भी अधिक समय से न्यूनतम 8.33% बोनस दिया जाता रहा है और न्यूनतम वेतन के भुगतान की दर बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। बोनस समीक्षा समिति की कार्रवाईयों के समय सी आई टी यू ने मांग की थी कि न्यूनतम बोनस में 10% वृद्धि की जाए तथा 20% की सीमा समाप्त कर दी जाए। तथापि इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसीलिये सी आई टी यू को इस प्रश्न पर श्रमिक वर्ग में अभियान चलाना चाहिये ताकि श्रमिकों के बोनस लेने के अधिकार में आवश्यक सुधार करने हेतु भारत में संयुक्त आंदोलन चलाया जा सके।

ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला

105. श्रमिक वर्ग पर नयी आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों में से एक दुष्प्रभाव ट्रेड यूनियनों पर हमलों का बढ़ना है। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये 'औद्योगिक शांति' को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ट्रेड यूनियन आंदोलन का दमन करने की आवश्यकता का दबाव डाला जा रहा है। भारत की यात्रा पर आने वाले विकसित पूंजीवादी देशों के राजदूत तथा व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के नेता श्रम कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं ताकि भारत में विदेशी पूंजी के मुक्त 'प्रवाह' को सुनिश्चित बनाया जा सके। उनके द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में किये जा रहे निर्लज्जतापूर्ण हस्तक्षेप के प्रति विरोध व्यक्त करने के स्थान पर भारत सरकार उन्हें बड़ी बेशर्मी से आश्वसत करती जा रही है कि उनके सभी निदेशों को कार्यरूप दिया जाएगा। प्रेस के माध्यम से निर्गम नीति को विधायी स्वीकृति देने के लिये बार-बार घोषणाएं की गई।

नया औद्योगिक सम्बन्धों वाला विधेयक भी श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार और संघर्ष के अन्य ट्रेड यूनियन रूपों पर अधिक अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही लाया गया है। ट्रेड यूनियन नेताओं पर भी अंकुश लगाने, यूनियनों के साथ उनके सम्बन्ध सीमित करने और यदि वे आपराधिक मामलों में वांछित हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक सम्बन्धों वाले पुराने विधेयक की अनेक गलत धाराओं को पुन: लागू किया जा रहा है। यद्यपि ट्रेड यूनियन आंदोलन के दबाव के कारण यह प्रश्न लम्बित हो गया है तथापि सरकार द्वारा इस विधेयक को संसद के

बजट सत्र में लाए जाने की सम्भावना है । ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपनी पूरी शक्ति के साथ इस विधेयक के विरोध में संघर्ष करना होगा ताकि सरकार को देश में ट्रेड यूनियन अधिकारों का दमन करने से रोका जा सके ।

संगठनात्मक रिपोर्ट पर बहस

106. नयी आर्थिक नीतियों के विरोध में संघर्ष करने के लिये मजदूर वर्ग में राष्ट्रव्यापी एकता स्थापित करने में हम सफल रहे हैं । तथापि इस एकता को उस समय तक सुदृढ़ नहीं किया जा सकता जब तक हम यथाशीघ्र ठीक ढंग से अपनी सांगठनिक दुर्बलताओं को दूर नहीं करेंगे । पिछले कई वर्षों से हम अपनी दैनिन्दन गतिविधियों में ही फंसे हुए हैं, ऐसी स्थिति में संगठन बनाने के काम की उपेक्षा हुई है और संगठन में अनेक गलत रुझान पनपने लगे हैं । संगठन पर कभी-कभर बहस करने से इस मामले को सुलझाया नहीं जा सकता । इसलिये जनरल कौंसिल की नागपुर बैठक में हमारी सांगठनिक दुर्बलताओं पर गहराई में जाकर अलग रूप से बहस करने की आवश्यकता को बुरी तरह अनुभव किया गया ।

कार्यसमिति की दो बैठकों तथा जनरल कौंसिल की एक बैठक में विशेष रूप से सांगठनिक रिपोर्ट के प्रारूप पर बहस की गई । कार्यसमिति की भुवनेश्वर बैठक में इसे अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व कई राज्यों में राज्य स्तरीय बहसें भी हुई थीं ।

107. सांगठनिक रिपोर्ट में अपनी सांगठनिक सम्भावनाओं और दुर्बलताओं को उसी संदर्भ में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है । जहां इसने सीटू केन्द्र, राज्य समितियों, जिला समितियों तथा उद्योगवार फेडरेशनों के कामकाज में व्याप्त दुर्बलताओं को उभारा है वहीं ट्रेड यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के दोषों की ओर भी संकेत किया है । उसने विस्तार में जाकर काडर के विकास, ट्रेड यूनियन शिक्षा एवं शोध, कामकाजी महिलाओं के मध्य अपने कार्यों तथा सीटू पत्रिकाओं के प्रश्न पर विचार किया है । रिपोर्ट के अंत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की एकता के प्रश्न पर विचार किया गया है और विशेष कार्यों का निर्धारण किया है । हमें अपनी सांगठनिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिये उन्हें कार्यरूप देना है ।

108. केन्द्र ने यह रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित की है जबकि राज्य समितियों ने उसे दूसरी क्षेत्रीय भाषा में अनुदित करने के लिये कदम उठाए हैं । यद्यपि इस प्रश्न पर अखिल भारतीय स्तर पर काफी बहस हो चुकी और हमारी सांगठनिक दुर्बलताओं के सम्बन्ध में कुछ जागरूकता भी आई है तथापि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिये कि हमें अभी संगठन में सुधार के सम्बन्ध में निकले ठोस परिणामों को देखना है । राज्य समितियों को विस्तृत आत्म आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जिसमें सम्बन्धित राज्यों में संगठन की स्थिति का समग्रता में परीक्षण किया गया हो और

रिपोर्ट में निश्चित किये गए कार्यों को कार्यरूप देने की प्रक्रिया का समय-समय पर अवलोकन किया जाए। सभी स्तरों पर योजनाबद्ध ढंग से कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है अन्यथा इसे कार्यरूप देने के लिये ठोस कार्रवाई किये बिना रिपोर्ट के लिये केवल मौखिक सहानुभूति व्यक्त करने का रुझान पनप हो सकता है। इससे हमारा उद्देश्य ही समाप्त हो कर रह जाएगा जिसकी चर्चा रिपोर्ट में की गई है। उद्योगवाद फेडरेशनों के कार्यों पर गहन विचार-विमर्श किये जाने की आवश्यकता है। कुछ फेडरेशनों ने पहले ही इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार करने तथा संगठन पर आत्म आलोचनात्मक रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है।

109. यद्यपि सीटू केन्द्र ने हिन्दी भाषी राज्य समितियों के नेताओं की एक बैठक बुलाने और इन राज्यों में सीटू की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से गतिविधियों की एक योजना तैयार करने का निर्णय किया था, तथापि अनेक कठिनाईयों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका। इस सम्मेलन के पश्चात् इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।

110. इस सम्मेलन में सांगठनिक प्रश्न पर विचार करने हेतु एक विशेष आयोग का गठन किया गया है। वह सांगठनिक दुर्बलताओं पर विस्तर में चर्चा करेगा ताकि आने वाले दिनों में मज़दूर वर्ग के गुंजायमान संगठन को बनाने के लिये वांछित कदम उठाए जा सकें।

111. सीटू केन्द्र में केन्द्रीय मुख्यालय में काम के बंटवारे की समीक्षा की है और पिछले निर्णयों की विशेष दुर्बलताओं को रेखांकित किया गया है। सैक्रेटेरिएट ने इन दुर्बलताओं को दूर करने और निर्णयों को कार्यरूप देने के लिये निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने का निर्णय किया है। निर्णयों को कार्यरूप देने सम्बन्धी प्रक्रिया पर निगरानी को सुनिश्चित बनाने के लिये कदम उठाए गए हैं ताकि केन्द्र संगठन के मोर्चे पर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यों की निगरानी कर सके।

कामकाजी महिलाओं में हमारा काम

112. सी आई टी यू अब कामकाजी महिलाओं के मध्य अपने काम को अधिक महत्व दे रहा है। सांगठनिक रिपोर्ट में कामकाजी महिलाओं के मोर्चे पर इसके कामों पर प्रकाश डाला गया है और कुछ अपनी दुर्बलताओं को इंगित किया गया है।

113. कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समिति नियमित रुप से अपनी बैठकें करती है तथापि उसमें सदस्यों की उपस्थिति की निरंतरता नहीं बनी। कुछ राज्य समितियों ने इस काम को गम्भीरता से लिया है जबकि अन्य समितियां

इस काम के महत्व को समझ नहीं रही हैं । कई यूनियनों में, जहां महिला कर्मचारियों की भारी संख्या है, अभी तक इस वर्ग में हमारे काम में मजबूती लाने के लिये महिलाओं की उपसमितियों का गठन नहीं किया गया है । स्थानीय यूनियनों में सक्रिय हुए बिना राज्य समन्वय समितियां प्रभावशाली ढंग से काम करने के समर्थ नहीं हो सकतीं ।

114. हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मध्य अपने कार्य में कुछ सुधार किया है । तथापि उनकी रोजगारी के आकार की अपेक्षा हमारी सदस्यता कम है । हमें उन राज्यों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाना होगा जहां हमारी इकाईयां नहीं हैं ताकि हम इस क्षेत्र में अपने काम में दृढ़ता ला सकें । यद्यपि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप उन्हें तुच्छ मौद्रिक लाभ प्राप्त हुए हैं तथापि उनकी जीवन-परिस्थितियां अभी भी खराब चली आ रहीं हैं और उनकी नियति में सुधार लाने हेतु कोई आंदोलन चलाया जाना चाहिये । हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में जिस एकता को स्थापित किया है उसे इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु और सुदृढ़ किया जा सकता है ।

115. इस मोर्चे पर महिला काडर के विकास के लिये महिला कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है । इसलिये समन्वय समिति ने महिला कार्यकर्ताओं के लिये अपनी पहली कक्षा 23 से 25 जुलाई 1993 तक हैदराबाद में लगाई थी । उसमें लगभग 40 महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यह बहुत सफल रही ।

116. मध्यम वर्गीय महिला कार्यकर्ताओं के मध्य हमारे काम के कुछ अच्छे परिणाम निकले हैं किन्तु असंगठित क्षेत्र में हमारी दुर्बलता पूर्वत: बनी हुई है । क्योंकि इस क्षेत्र में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या कार्यरत है, इसलिये सी आई टी यू ने इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने का निर्णय किया है । असंगठित श्रमिकों के मध्य अपने काम में मजबूती लाने के लिये हमें कामकाजी महिलाओं के मध्य अपनी गतिविधियों का ठीक ढंग से प्रसार करना चाहिये ।

117. कामकाजी महिलाओं का अखिल भारतीय सम्मलन सीटू सम्मेलन से पूर्व 2 मार्च, 1994 को पटना में होगा । सम्मेलन द्वारा कामकाजी महिलाओं के मध्य हमारे काम में सुधार लाने हेतु उचित कदम उठाए जाएंगे । कामकाजी महिलाओं पर विशेष आयोग उन ठोस उपायों का पता लगाएगा जिससे कामकाजी महिलाओं के मध्य हमारे काम की दुर्बलता को दूर किया जा सके । सी आई टी यू की सदस्य संख्या को बढ़ाने के लिये हमें कामकाजी महिलाओं के बीच भी अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिये प्रयास करने चाहियें ।

ट्रेड यूनियन एकता को सुदृढ़ करने के लिये संघर्ष

118. निकट अतीत में हमारे द्वारा चलाए गए अथक संघर्षों के दौरान देश में असाधारण ट्रेड यूनियन एकता स्थापित की गई है । इसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । हमारे अपने अस्तित्व के संघर्ष को अधिक प्रभावशाली बनाने के

लिये इस आंदोलन को और सुदृढ़ करना एक आवश्यक कार्य बन गया है ।

119. वर्तमान परिस्थितियों में हम मुद्दों के आधार पर पूरे मजदूर वर्ग को एकताबद्ध करने के योग्य हैं जैसा कि इस्को कर्मचारियों के पूंजी-विनिवेश और निजीकरण विरोधी संघर्ष में देखा गया है । इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 42 मिलों को बंद करने और उनके 70,000 श्रमिकों को नौकरी से बाहर निकाल देने के प्रयास के विरोध में संयुक्त समिति का गठन किया गया है । उस समिति में अन्य ट्रेड यूनियनें के अतिरिक्त इंटक तथा बी एम एस भी शामिल हैं । संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इसमें उक्त मिलों के श्रमिकों को 5 मई को दिल्ली में संयुक्त जन सभा करने के आह्वान किया गया है । रेलवे कर्मचारी आंदोलन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं तथा रक्षा विभाग कर्मचारियों के साथ एकता करने के परिणाम स्वरूप भारत सरकार की कुछ रियायतें देने पर विवश होना पड़ा है । अभी अनेक मांगों का निपटारा किया जाना है । इसके लिए संघर्ष करना होगा तथा एकता और मजबूत करनी होगी ।

120. कार्यसमिति की भुबनेश्वर बैठक में हमने एक उद्योग में एक यूनियन बनाने के प्रश्न पर विचार किया है । क्योंकि सभी सम्बद्धताओं वाले कार्यकर्ताओं में एकता स्थापित करने की मांग बढ़ रही है, इसलिये एक उद्योग में एक यूनियन बनाने की मांग को कार्यसूची में शामिल किया गया है । हमने सही रूप में ट्रेड यूनियनों की लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली और मजदूर वर्ग के हितों के प्रति ट्रेड यूनियनों की वफादारी के पक्षों पर बल दिया है ।

यदि सभी घटक संगठनों में इन पक्षों पर उचित सहमति हो जाती है तो हमने उस स्थिति में संयुक्त उद्योगवाद फेडरेशनें बनाने के प्रति अपनी तत्परता व्यक्त की है ।

121. पिछले सम्मेलन में हमने अपने मंच से भारतीय ट्रेड यूनियनों का परिसंघ बनाने की धारणा को लोकप्रिय बनाने पर बल दिया था ताकि ऐसे परिसंघ का गठन करने के लिये देश भर में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके ।

122. परिसंघ बनाने के हमारे नारे के प्रत्युत्तर में कुछ विशेष केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का तुरंत विलीनीकरण करके एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र बनाने का नारा दिया है । तथापि कठोर यथार्थ के दृष्टिगत आज एकता की आवश्यकता है । यह एकता विभिन्न मुद्दों पर जिनका सामना श्रमिक वर्ग को करना पड़ रहा है ट्रेड यूनियन नीतियों के सम्बन्ध में भी होनो चाहिये । यह एकता परिसंघ की स्थापना करके ही हो सकती है ।

परिसंघ का सफल कामकाज देश में एकमात्र राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन केन्द्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा ।

123. यह रेखांकित किया जाना चाहिये कि हमारी यूनियनों ने ट्रेड यूनियनों के परिसंघ की हमारी अपनी धारणा को लोकप्रिय बनाने के लिये पर्याप्त काम नहीं किया है। अनेक उद्योगवाद स्वतंत्र फेडरेशनें इस धारणा का स्वागत करेंगी क्योंकि इससे वे एकीकृत ट्रेड यूनियन आंदोलन की परिसंघ में शामिल हो सकेंगी। देश में इस प्रश्न पर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

124. देश में ट्रेड यूनियन एकता के प्रश्न पर बहस करने के लिये सीटू केन्द्र ने एक विनम्र समारम्भ किया है जबकि उसके द्वारा कामरेड बी टी रणदिवे के 89 वें जन्म दिवस के अवसर पर 20 दिसम्बर 1993 को दिल्ली में ट्रेड यूनियन एकता के मुद्दों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुझे यह रेखांकित करते समय प्रसन्नता हो रही है कि सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने उस संगोष्ठी में भाग लिया था। आशा है कि इस बहस से देश में ट्रेड यूनियन एकता के विकास और मजबूती की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।

125. सी आई टी यू की विभिन्न समितियों द्वारा देश भर में ऐसे ही प्रयास किये गए हैं। हमारी उद्योगवाद फेडरेशनें जहां कभी भी सम्भव हो सके ऐसी ही उद्योगवाद वार्ता को आरम्भ कर सकती हैं।

126. हमें मजदूर वर्ग की एकता को विकसित करने की दिशा में बनाई गई ऐसी अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहिये। यदि मजदूर वर्ग ने देश की वर्तमान परिस्थितियों में अग्रणी भूमिका निभानी है तो ऐसी एकता की अत्याधिक आवश्यकता है।

बी.टी.आर स्मारक न्यास

हमने पिछले सम्मेलन में अपने संस्थापक अध्यक्ष एवं शिक्षक कामरेड बी टी रणदिवे की स्मृति समुचित स्मारक बनाने का निर्णय किया था। सी आई टी यू ने बी टी आर स्मारक कोष के लिये अपनें सभी सदस्यों तथा हमदर्दों को एक-एक दिन का वेतन देने का आह्वान किया था। कामरेड समर मुखर्जी की अध्यक्षता में पहले ही बी टी रणदिवे स्मारक न्यास की स्थापना की जा चुकी है। तथापि योगदान के प्रति साथियों का प्रच्युत्तर आशा के अनुरूप नहीं रहा है। हम अभी तक लगभग 15 लाख रूपये इकट्ठे कर सके हैं जबकि स्मारक बनाने में दो करोड़ रूपये से भी अधिक खर्च आयेगा। हमें कोष इकट्ठा करने के लिए गम्भीर प्रयास करने होंगे ताकि हम यथाशीघ्र स्मारक का निर्माण कर सकें। स्मारक में एक अच्छा पुस्तकालय ट्रेडयूनियन पाठशाला का प्रबंध करने तथा शोध संस्थान खोलने का भी विचार है। शहरी विकास मंत्रालय ने स्मारक के लिए भूखंड का आवंटन कर दिया है किंतु उसका कब्जा लेने के मार्ग में कुछ अवरोध हैं इस मामले को सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि हम यथाशीघ्र स्मारक के लिए आवंटित भूखंड का अधिग्रहण कर सकें।

हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

128. प्रसन्नता का विषय है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं और हम अधिक से अधिक संगठनों के साथ भ्रातृ सम्बन्ध सथापित करते जा रहे हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जबकि अमरीकी साम्राज्यवादी हथकण्डों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की अत्याधिक आवश्यकता है, इन बढ़ रहे भ्रातृ सम्बन्धों से हमें मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों में अधिक गम्भीर भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी।

129. हम समाजवाद देशों के साथ मैत्री सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाते के काम को उच्च प्राथमिकता देते हैं। पिछले सम्मेलन के पश्चात् ट्रेड यूनियनों की अखिल चीनी फेडरेशन के आमंत्रण पर हमने चीन में अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था। इससे हम चीन की वर्तमान स्थिति उनके और समाजवादी निर्माण के उनके अभियान के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके हैं। ए सी एफ टी यू पिछले दो वर्षों से विकास की समस्याओं पर एशियाई संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है। इससे एशियाई देशों की ट्रेड यूनियनों को एक दूसरी के साथ अपने विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने और ज्ञानवर्धन करने में सहायता मिली है। हमने दोनों संगोष्ठियों में भाग लिया और उसकी कार्रवाई से लाभान्वित हुए हैं। जब मुझे सितम्बर 1992 में एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिये चीन जाने का अवसर मिला तो मैंने वहां चीनी ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ विभिन्न देशों में ट्रेड यूनियन आंदोलन की समस्याओं के ऊपर गहन विचार-विमर्श किया था। चीन के एक उच्च अधिकार प्राप्त तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 1993 के पूर्वाध में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की थी। उसकी नेतृत्व ए सी एफ टी यू के उपाध्यक्ष कामरेड जांग डिन गुआ कर रहे थे। प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की सभी बड़ी यूनियनों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया था। इससे भारत और चीनी ट्रेड यूनियनों के मध्य मैत्री पूर्ण सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली थी। इससे पूर्व श्रीमती (डाक्टर) कुटनिस के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल दिसम्बर 1992 में भारत आया था। सी आई टी यू ने आतिथेय के कत्ताव्यों का निवर्हन किया। भारत की सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से उनके सम्मान में संयुक्त रूप से एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया।

130. सी टी सी (क्यूबा) के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख कामरेड जोवागिन बर्नाल की नवंबर 1993 के शुरू में हुई भारत यात्रा अत्यंत संफल रही थी। सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने उनका स्वागत किया था। क्यूबा किस प्रकार अमरीकी धौंस (भयादोहन) का वीरतापूर्वक सामना कर रहा है, इसका प्रभावशाली वर्णन कामरेड बर्नाल ने किया था। कलकत्ता में सी आई टी यू की राज्य समिति की ओर से अच्छा कार्यक्रम किया गया।

131. वियतनाम और कोरिया के साथ हमारे सम्बन्धों में और सुधार हुआ है। हम समय-समय पर उनके संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं।

132. फिलीपीन्स की किलूसांग मायो उनो (के एम यू) प्रति वर्ष मई दिवस के अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता समारोह का आयोजन करती है। हम 1992 तथा 1993 में उन समारोहों में शामिल हुए और हमने उस संगठन के अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।

133. इसी अवधि में ट्रेड यूनियनों की आस्ट्रेलियन कौंसिल के साथ हमारे सम्बन्धों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आस्ट्रेलिया में ट्रेड यूनियनें के भारतीय उपमहाद्वीपीय सम्मेलन में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया था। उसमें सांस्कृतिक मोर्चे के दो कर्मी भी थे। यह सम्मेलन दिसम्बर 1992 में हुआ था। इस सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की शर्तों का विरोध किया था। कामरेड चित्तब्रत मजूमदार ने कुआला लम्पर में समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। यह बैठक सितम्बर 1993 में हुई थी। उसमें बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन का निरीक्षण भी किया गया। आस्ट्रेलिया की ट्रेड यूनियनों के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने भारत की यात्रा की। वह बम्बई, दिल्ली, धनबाद और कलकत्ता गया जहां उसने सी आई टी यू नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। भारत महाद्वीपीय क्षेत्र का अगला सम्मेलन अक्तूबर 1994 में होगा। उसमें भारत को 4 सीटे आवंटित की गई हैं।

134. दक्षिण अफ्रीका ट्रेड यूनियनों की कांग्रेस (सी ओ एस ए टी यू) का एक चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल मई 1992 में भारत आया। इसका प्रायोजन सी टी यू सी ने किया था। प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य अनेक केन्द्रों में गये जहां सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उनका स्वागत किया गया। हमने उनके सम्मान में बहुत शानदार स्वागत समारोह का आयोजन किया जिसमें सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। रंगभेद विरोधी भारतीय ट्रेड यूनियन समिति कीओर से दिल्ली के ए एन सी कार्यालय को हैवी ड्यूटी फोटो कापियर भेंट किया गया।

135. सी आई टी यू के नवंबर 1993 में खेत मजदूर संघ के सम्मेलन के लिये अपना तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बंगला देश भेजा था। प्रतिनिधिमण्डल ने वहां की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श किया। इससे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए।

136. हमने 1991 में रूस की स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के फेडरेशन के प्रतिनिधिमण्डल के साथ-साथ उज़्बेकिस्तान और कज़ाखस्तान के प्रतिनिधिमण्डलों के आतिथेय के कत्र्तव्यों का निर्वहन किया था। सी आई टी यू तथा उक्त तीनों संगठनों के मध्य भ्रातृ सम्बन्ध विकसित करने के लिये सहमति हुई। भारत से एक संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल 1993 में उज़्बेकिस्तन तथा कज़ाखस्तान की यात्रा पर गया था। सी आई टी यू के सदस्य भी उस प्रतिनिधिमण्डल में शामिल थे।

१३७. इराक की ट्रेड यूनियनों की जनरल फेडरेशन के आमंत्रण पर हमने एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल वहां

भेजा। अमरीकी आक्रमक कार्रवाईयों के विरोध में इराकी ट्रेड यूनियनों एवं जनता के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। यद्यपि प्रतिनिधिमण्डल का प्रवास बहुत कम समय का था तथापि सभी स्थानों पर उसका भारी स्वागत किया गया। वहां से वापसी पर अम्मान में प्रतिनिधिमण्डल ने वहां के ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण वार्ता की।

138. नेपाली ट्रेड यूनियनों की जनरल फेडरेशन का एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल 1993 में भारत आया। उसने परस्पर सहयोग के सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत की। कामरेड विमल रणदिवे तथा जे एस मजूमदार ने 1993 में काठमंडू में आयोजित आई एल ओ की संगोष्ठी में भाग लिया था। दोनों ने जी ई एफ ओ एन टी नेताओं के साथ भेंट की और परस्पर सहयोग बढ़ाने के विषय पर विचार विमर्श किया। एशियाई महिला समिति (सी ए डव्ल्यू) की ओर से 1993 के द्वितीय भाग में नेपाल में महिला ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया। सीटू ने उसमें भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था।

139. कामरेड एम. के. पंधे ने अन्तर्राष्ट्रीय खदान संगठन के तृतीय सम्मेलन में भाग लिया था। यह सम्मेलन 9-12 मई 1993 तक अल्जीरिया में हुआ था। वह आई एम ओ की कार्यकारिणी के लिये चुने गए। उन्होंने 30-31 नवंबर 1993 को पांचवी बैठक में भाग लिया। उन्हें सेफटी कौंसिल की एशियाई समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु राष्ट्रीय सेफटी कौंसिल के लिये मनोनीत किया गया। यह बैठक सितम्बर 1992 को सियान में हुई थी।

140. ट्रेड यूनियनों की सिलोन फेडरेशन के माहसचिव एस डब्ल्यू सुबासिंधे 1992 में भारत की यात्रा के समय सी आई टी यू नेताओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया।

141. सी जी टी फ्रांस के अन्तर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख 1992 में भारत आये। उन्होंने सी आई टी यू नेताओं के साथ परस्पर सहयोग के विषय पर विचार विमर्श किया। सी जी टी फ्रांस भारतीय मजदूरों के साथ विभिन्न संघर्षों में एकजुटता व्यक्त करती रही है। उसने महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों के लिये सहायतार्थ सी आई टी यू के माध्यम से 1000 अमरीकी डालर भेजे थे। फ्रांस, इटली, ग्रीस और डेनमार्क की कुछ अन्य स्थानीय यूनियनों ने भारत में मजदूर वर्ग का उसके संघर्षों में समर्थन किया है।

142. पिछले कुछ समय से कामनवेल्थ ट्रेड यूनियन कौसिल के साथ हमारा सहयोग बढ़ा है। हमने सी टी यू सी के सहयोग से प्रशिक्षण विधियों पर अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया है। हमने नयी प्रौद्योगिकी के दुष्प्रभावों और मजदूरों के लिये अस्वस्थ्यकर स्थितियों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया है। यू के की अनेक यूनियनें समय-समय पर सी आई टी यू के साथ सम्पर्क बनाए रखती हैं।

143. जापान के 'ज़ेनरोरेन' और 'मिंकोरोरेन' के साथ हमारे भ्रातृ सम्बन्धों में निरंतर वृद्धि होती रही है । दिल्ली में डब्लयू एफ टी यू के कार्यालय के पुन: खुल जाने के पश्चात् हम उनके (कार्यालय) साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं । डब्ल्यू एफ टी यू के महासचिव कामरेड ज़ानीकोव ने 1991 में अपनी भारत यात्रा के समय हमारे साथ परस्पर सहयोग बढ़ाने के प्रश्न पर विचार विमर्श किया था ।

144. उस सम्मेलन में विश्व भर से आए प्रतिनिधिमण्डलों की उपस्थिति से हमारे भ्रातृ ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ सम्बन्धों का बढ़ते चले जाने ही प्रतिबिम्बित होता है । हम इन सम्बन्धों को अपने हदय में संजोए रखेंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारे सम्बन्ध और सुदृढ़ होंगे । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थतियों में इन सम्बन्धों से न केवल हमें प्रोत्साहन मिलता है अपितु हमारे अंदा आत्म विश्वास भी पैदा होता है । हमारा निश्चय और भी दृढ़ हो जाता है कि मजदूर वर्ग का आंदोलन एक बार फिर विश्व भर में नयी शक्ति एवं शान के साथ आगे बढ़ेगा । यह नारा 'सभी स्तर कें मजदूर एक हों' निरंतर हमारी सांझी विरासत और संघर्षों को रेखांकित करता रहेगा !

145. भ्रातृ सम्बन्धों और मैत्री को सुदृढ़ करने के लिये हमें अपने अन्तर्राष्ट्रीय विभाग को और सुदृढ़ करना होगा । तभी हम विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय एकजुटता को विकसित करने की ओर अधिक ध्यान दे सकेंगे । इस सम्मेलन के पश्चात् हमें इस काम को अपने प्राथमिकता वाले कामों की भांति की लेना होगा !

बड़े वर्ग संघर्षों की ओर

साथियों,

146. पिछले तीन वर्षों में हमने अनेक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएं हैं और नरसिम्हा राव की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीतियों, साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों के विरोध में संघर्ष किये हैं । इन संघर्षों में मजदूर वर्ग धीरे-धीरे अग्रणी भूमिका निभाने के लिये आगे रहा है । तथापि यदि हमने देश की एकता और अखण्डता व आत्मनिर्भरता की रक्षा करनी है, तो हमें काफी संघर्ष करना होगा ।

147. ज्यों-ज्यों हमारा आंदोलन सुदृढ़ता और विशालतर होता जा रहा है, इसे और अधिक विकसित किये जाने की आवश्यकता है । आंदोलन की अनिश्चित भूमिका से उत्पन्न् अपनी दुर्बलताओं को दूर किये बिना हम इस कार्य का सम्पादन नहीं कर सकेंगे । पूरी दृढ़ता के साथ हमें हर प्रकार से अनिश्चय की दुर्बलता को दूर करना होगा । हमें किसी भी स्थिति में पूंजीवादी हमलों के दबावों के आगे झुकना नहीं होगा । इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि सभी सम्बद्धताओं के कार्यकर्ता दृढ़ संघर्ष छेड़ना चाहते हैं । हमें इसका लाभ उठा कर जहां तक सम्भव हो सके अपने संग्रर्ष

को मजबूत एवं विशाल बनाना चाहिये। इस सम्बन्ध में 7 दिसम्बर 1993 की टैलीकाम हड़ताल तथा 31 जनवरी 1994 को सीटू द्वारा संगठित की गयी अखिल भारतीय कोयला मजदूर हड़ताल जिसमें बहुसंख्य श्रमिकों तथा दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ सम्बद्धता रखने वाले श्रमिकों ने भाग लिया था, की सफलता, इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं।

148. हमें किसान-मजदूर गठजोड़ कर अधिक बल देना होगा। यह हमारे लिये मात्र एक नारा ही न रहे अपितु किसान संगठनों के साथ निकट सम्बन्ध एवं एकता स्थापित करके मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन को ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष को सुदृढ़ करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहियें। लाखों किसानों को लामबंद किये बिना हमारा संघर्ष जुझारू चरित्र वाला नहीं बन सकता। खेत मजदूर संगठनों के साथ निकट सहयागे को और बढ़ाने पर विशेष बल देना होगा। भारत सरकार की आर्थिक नीतियों को परास्त करने और साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों को मुंह तोड़ उत्तर देने में महिला, छात्र और युवा आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

149. आयोगों में विस्तृत बहस जो हम इस सम्मेलन में कराने जा रहे हैं, के माध्यम से उन ठोस कदमों का निर्णय करना सम्भव हो सकेगा, जिन्हें हम अपने आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिये उठा रहे हैं। मुझे आशा है कि जब हम सम्मेलन का समापन करेंगे तब हम अपनी गतिविधियों के भावी कार्यक्रम के निर्धारण के लिये निश्चित निर्देशावली बनाने में सक्षम होंगे।

150. हमारे देश की जनता द्वारा सभी राज्यों में भारी प्रदर्शनों के आह्वानों को जो शानदार प्रत्युत्तर दिये हैं उससे लोगों की तत्परता स्पष्ट रूप से झलकती है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देश के सभी भागों में फौरी तौर पर जन कार्रवाईयों में भाग लेना होगा और 5 अप्रैल को देश की समस्त मेहनतकश जनता के एक शक्तिशाली प्रदर्शन की तैयारी करनी होगी जिसका आह्वान जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया है।

151. जब हम बड़े कार्यों में व्यस्त हों तब भी हमें इस तथ्य को दृष्टिलोप नहीं करना चाहिये कि विहिप के कठमुल्लावार देश में साम्प्रदायिकता की नयी लहर बनाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने राम मन्दिर का निर्माण करने की धमकी दी है। उसी समय हमें भी जन-एकता के लिये भारी प्रदर्शन की तैयारी करनी चाहिये। अत: इस मामले में हमें अपनी चौकसी को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

152. राष्ट्रीय मंच 5 अप्रैल के पश्चात् संघर्ष के एक और दौर की तैयारी करेगा। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक भारत सरकार की नीतियों को पूर्णतया परास्त नहीं किया जाता।

साथियो,

153. आईये, हम सत्ताधारी वर्गों और देश में विद्यमान कठमुल्लावादी शक्तियों की चुनौती को स्वीकार करें। बजट पूर्व

मूल्य वृद्धि को झेल रही जनता रेलवे बजट और आम बजट के पश्चात् और कटु जो जाएगी । उनके आगे इन नीतियों का, जिनके कारण उसके जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है, प्रतिकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा । उस समय उसे (जनता) सही नेतृत्व और सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होगी जो उसे संघर्ष का मार्ग दिखा सके ।

154. जन संगठनों ने राष्ट्रीय मंच में राष्ट्रव्यापी संयुक्त संघर्षों में जनता को लामबंद करने की क्षमता विद्यमान है । आईये, हम स्वयं को आने वाले संघर्षों के लिये अच्छी तरह तैयार करे ताकि हम इस पवित्र काम में अपनी प्रभावशाली भूमिका को निभा सकें ।

* *मजूदर वर्ग की एकता-अमर रहे।*

* *नयी आर्थिक नीतियों और साम्प्रदायिकता विरोधी संयुक्त संघर्षों में मजदूर वर्ग, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं तथा बुद्धिजीवियों की एकता-अमर रहे।*

* *साम्राज्यवाद, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व बैंक एवं कोष के निदेशों के विरूद्ध संघर्ष : अमर रहें।*

* *सी आई टी यू का आठवां सम्मेलन - अमर रहे।*

* *दुनिया भर के मजदूरों-एक हो जाओ।*

एम के पंधे

महासचिव

सी आई टी यू